चिंतन

ट्रंपकाल में अमेरिका पर रहेंगी दुनिया की निगाहें

अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार ताजपोशी वैश्विक स्तर पर ट्रंपवाद की भी पिच से शुरूआत है। अमेरिका फर्स्ट, संरक्षणवाद से प्रेरित ट्रंपवाद से अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी, यह वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन ट्रंपवाद अमेरिका और शेष विश्व के लिए बहुत उम्मीद नहीं जगाता है। महाशक्ति के रूप में वैश्विक संस्थाओं के संरक्षण और वैश्विक मसलों के हल को लेकर अमेरिका की अपनी एक साख रही है, ट्रंपवाद इसमें बाधा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस साख पर आंच आई, अब दूसरे कार्यकाल में अनुभवी ट्रंप अमेरिका के महाशक्तित्व को कैसे पुनस्थापित करते हैं, यह भी समय के साथ ही पता चलेगा। अभी विश्व में सबसे अधिक चर्चा ट्रंप के शपथग्रहण की है। अमेरिका ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को ट्रंप के शपथग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। माना जा रहा था कि नरेन्द्र मोदी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है तो अमेरिका पीएम मोदी को विशेष आमंत्रण देगा। पर अमेरिका ने कूटनीतिक दांवपेच और चीन से अपने संबंध सुधारने के एजेंडे के तहत चीन को तरजीह दी। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी निमंत्रण को गंभीरता से नहीं लिया और खुद न जाकर अपने दूत को ट्रंप के शपथग्रहण में भेज दिया। चीनी राष्ट्रपति के नहीं आने से न ट्रंप की अच्छा लगा होगा और न ही अमेरिका को। कूटनीति के जानकार मान रहे थे कि चूंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका व चीन के बीच ट्रेडवार अपने चरम पर था, इसलिए इस कार्यकाल में ट्रंप चीन से अमेरिका के संबंध को सामान्य करने की दिशा में शपथग्रहण कूटनीति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का शुभकामना संदेश लेकर ट्रंप के शपथग्रहण समारोह में पहुंचे। अमेरिकी चुनाव में जबरदस्त जीत मिलने के बाद 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के कुछ हफ्तों के बाद दुनिया को यह पता चल जाएगा कि उनका दूसरा कार्यकाल विश्व के लिए कैसा रहने वाला है? ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और ग्रीनलैंड व पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने की बात कही है। उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करने की भी बात कही है। उन्होंने रूस व यूक्रेन युद्ध व इजराइल व हमास जंग भी खत्म करने की बात दोहराई है। पश्चिम एशिया हिंसक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। ट्रंप ने ये सब बातें आज 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण से पहले कही हैं, जिससे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की झलक देखने को मिली है। ट्रंपकाल में एलन मस्क जैसे अरबपति उद्यमियों की सरकार में अहमियत बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अवैध प्रवासी को लेकर भी अमेरिका का रुख सख्त रहेगा। ट्रंप ने अपनी टॉप टीम में क्रिस्टी नोएम, टॉम होमन, मार्को रूबियो, माइकल वाल्ज्ज, एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, तुलसी गबार्ड, हावर्ड लुटनिक, स्कॉट बेसेंट जैसे अनुभवी व विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया है। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे पूर्व यूएसए राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में रिपब्लिकन सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने और विश्व में अपनी साख स्थापित करने की बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का चार साल का कार्यकाल न केवल यह निर्धारित करेगा कि अमेरिका अपने घरेलू मुद्दों से कैसे निपटता है, बल्कि दुनिया में उसकी हैसियत को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

विश्लेषण
विकेश कुमार बडोला

वित्तीय सुरक्षा बढ़ाएगी स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना एक क्रांतिकारी योजना है। यह कृषि क्षेत्र का समयानुकूल सशक्तिकरण करने का वृहद आधार बनेगी। गांवों, छोटे-छोटे नगरों एवं कस्बों में स्थानीय कृषकों और श्रमिकों के जो भी कृषि भूखण्ड व आवासीय भूमि है उसका अब तक समुचित मापन नहीं था। पीढ़ियों से लोगों के पास होने के बाद भी इनका अभिलेखीकरण नहीं किया गया था। स्वामित्व-अभिलेख की अखिल भारतीय प्रामाणिकता होने के उपरान्त ग्रामीण-जगत की संपूर्ण जीवन व्यवस्था में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग अपनी भूमि और घरों के वास्तविक, प्रामाणिक व प्रलेखमूलक स्वामी / स्वामिनी होंगे। यह गांवों में वित्तीय सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।

वर्ष 2020 के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ हुई भू-स्वामित्व व भू-अधिकार योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के क्रम में 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने लगभग 65 लाख की संख्या में स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने इस क्रांतिकारी योजना के तात्कालिक एवं दूरगामी लाभों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री के अनुसार, ग्रामीण व छोट-छोटे नगरों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिलने के बाद लाखों लोगों ने इस आधार पर बैंकों व अ-बैंकिंग संस्थानों से अपनी जरूरत का ऋण प्राप्त किया है। लोगों ने ऋण का उपयोग अपना व्यापार-उद्योग आरंभ करने में किया। इन लोगों में अधिसंख्य कृषक हैं, जिनके लिए स्वामित्व संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा का शासकीय आश्वासन है। भविष्य में भूमि स्वामित्व व भूमि अधिकार कार्ड के आधार पर सौ लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त होगा। मूलतः ये कार्ड गांवों के विकास की नींव बनेंगे। कार्डधारकों को ऋण और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। अभी संपत्ति कार्डों का वितरण छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख के पचास हजार से अधिक गांवों के लाभार्थियों को किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.24 करोड़ व्यक्तियों के पास संपत्ति स्वामित्व कार्ड होंगे। दुनियाभर में देशों के महानगरों व नगरनिगम शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त सुदूरवर्ती ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वामित्व व भूमि अधिकार मिलना आरंभ से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस संदर्भ में कई वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन किया था, जिसमें यही निष्कर्ष निकला कि अनेक देशों में लोगों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व के लिए कानूनी प्रलेख नहीं हैं।

स्वामित्व योजना एक क्रांतिकारी योजना है। यह कृषि क्षेत्र का समयानुकूल सशक्तिकरण करने का वृहद आधार बनेगी। गांवों, छोटे-छोटे नगरों एवं कस्बों में स्थानीय कृषकों और श्रमिकों के जो भी कृषि भूखण्ड व आवासीय भूमि है उसका अब तक समुचित मापन नहीं था। पीढ़ियों से लोगों के पास होने के बाद भी इनका अभिलेखीकरण नहीं किया गया था। जब भी जिस कृषक, श्रमिक और गांव के गरीब व्यक्ति को अपनी भूमि की नाप-जोख कर उसके अभिलेख बनवाने की आवश्यकता होती, तो वह गांव के प्रधान या प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता लेकर उसको निश्चित मुद्रा का भुगतान करके अपना भूमि से संबंधित कार्य करवाता था। इस प्रक्रिया को पंचायत से लेकर तहसील स्तर तक इतना जटिल और मकड़जालीनुमा बना दिया गया था कि अधिसंख्य ग्रामीण अपनी भूमि का पंजीकरण-अभिलेखीकरण करवाने के लिए हमेशा हतोत्साहित रहे। करोड़ों की जनसंख्या में से यदि हजारों-लाखों ग्रामीण गरीब लोग भी अपनी-अपनी भूमि का पंजीकरण-अभिलेखीकरण स्थानीय अवैध प्रक्रिया के अन्तर्गत करवाते थे तो इससे ही दलाली के रूप में बड़ी मुद्रा का लेन-देन होता आया था। यह दुर्व्यवस्था अब भी चल रही है और इसीलिए भूमि का मापन कर उसके स्वामित्व

अभिलेख लोगों को देने का एक अति सहज-सरल शासकीय कार्य अत्यंत जटिल बना हुआ है।

घरों और खेतों का अभाशी व मौखिक स्वामित्व ग्रामीणों के लिए अनेक प्रकार से अनुपयोगी और आधुनिक जगत में विकास की धारा से वंचित रहने का कारण था। ग्रामीण एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में लोगों के पास भू स्वामित्व के कानूनी प्रमाण व प्रलेख न होने के कारण, लाखों एकड़ की भूमि का पूंजीगत उपयोग नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी की सहायता से भूमि का मापन होने, ड्रोन कैमरे से गांव की संपूर्ण भूमि का मानचित्र बनाने के साथ-साथ एक ग्रामीण की समग्र भूमि का मानचित्र बनाकर उसका स्वामित्व-अभिलेख बनने और इस स्वामित्व-अभिलेख की अखिल भारतीय प्रामाणिकता होने के उपरान्त ग्रामीण-जगत की संपूर्ण जीवन व्यवस्था में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग अपनी भूमि और घरों के वास्तविक, प्रामाणिक व प्रलेखमूलक स्वामी / स्वामिनी होंगे। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत उनके स्वामित्वधारण की स्वीकार्यता अखिल भारतीय ही नहीं अपितु अखिल वैश्विक होगी। कृषक, श्रमिक, ग्रामीण और छोट-छोटे काम-धंधे करनेवाले करोड़ों लोग अब अपनी भूमि के प्रामाणिक शासकीय प्रलेखों के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सत्यप्रमाणित स्वामित्व-प्रलेखों के होने पर अब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं लोगों को ऋण लेने से वंचित नहीं रख सकतीं।

स्वामित्व-प्रलेख लोगों के लिए प्रसन्नता का कारण बनेंगे। अभी तक अधिसंख्य ग्रामीण भूमि पर लोगों का आभासी और मौखिक स्वामित्व ही है। इस कारणवश दुर्जन लोग दूसरे की भूमि हथियाने या दूसरे की भूमि के कुछ हिस्से का अपने स्वामित्व में होने का दावा करते हैं, जबकि इसका कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं होता। स्वामित्व योजना के पूर्णरूपेण लागू हो जाने के बाद इस प्रकार की अवैध दावेदारी बंद हो जाएगी। जब सभी लोगों को उनकी भूमि से संबंधित स्वामित्व अभिलेख प्राप्त हो जाएंगे तो ग्रामीण स्तर पर भूमि को लेकर उभरनेवाले विवाद, संघर्ष और झगड़े-झंझट सब रुक जाएंगे। ग्रामीण व्यक्ति जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा कि उसकी भूमि विधिक और प्रामाणिक रूप में उसी की है तथा उसके पास इसका प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है, तो वह भूमि के स्वामित्व के आधार पर अपनी संभावित कृषि एवं व्यापार योजनाओं को साकार करने के लिए एकनिष्ठ हो सकेगा।

जिस प्रकार चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की मानसिकता से ग्रस्त हैं और आए दिन सीमाक्षेत्र की भूमि को लेकर उनके द्वारा कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न किया ही जा रहा है, तो इस स्थिति में सीमा-क्षेत्रों की भूमि पर स्थानीय लोगों के लिए स्वामित्व अभिलेख बनाया जाना अति आवश्यक है। यदि लोगों के अधिकार वाली सीमा-क्षेत्र की भूमि का नागरिक स्वामित्व बना रहेगा, तो अन्य देशों के साथ सीमा-क्षेत्रों के विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में हमारा देश समुचित साक्ष्यों के साथ तैयार होगा, जो हमारे लिए हर दृष्टि से लाभकारी होगा। जैसे-जैसे देश में लोगों को उनकी भूमि का स्वामित्व शासकीय प्रमाणों व प्रलेखों के माध्यम से मिलता जाएगा, वैसे-वैसे देश में अर्थव्यवस्था एक नए दिशाबोध के साथ प्रगतिवान होगी। यह कुछ वर्षों में न केवल सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान देगी, अपितु प्रति व्यक्ति आय में भी अत्यधिक वृद्धि करेगी। इस योजना को अखिल भारतीय भूमि सुधार की वृहद नीति से भी जोड़ा जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

महाकुंभ

आर. के. सिन्हा

क्यों करोड़ों श्रद्धालु जुड़ते हैं

प्रयागराज में संगम पर महाकुंभ अपनी रौ में है। पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान विगत 13 जनवरी को हुआ। देश के कोने-कोने से भक्त प्रयागराज आ रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। क्या आप भी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे? अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपने को भाग्यशाली मान सकते हैं। आपको यहां कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यज्ञ, हवन, और कीर्तन। ये अनुष्ठान वातावरण को शुद्ध करते हैं और श्रद्धालुओं को भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने का अवसर देते हैं। कुंभ मेला एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है जो लोगों को भगवान के करीब लाता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह आत्म-अनुशासन और त्याग के महत्व को दर्शाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो लाखों लोगों को एक साथ आने और अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। कुंभ मेले का आयोजन उन स्थानों पर होता है जहां पवित्र नदियों का संगम होता है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयाग में। अब बात प्रयागराज और कुंभ के संबंधों की भी। प्रयाग (बहु-यज्ञ स्थल) को कहा जाता है। प्राचीन काल से ही 'तीर्थराज' के रूप में प्रसिद्ध हुआ यह संगम स्थल पर हुए अनेक यज्ञों की वजह से, जिनमें पहला यज्ञ किया सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के तत्काल बाद। यज्ञवेदी है गंगा, यमुना और गुप्त रूप से बहने वाली सरस्वती की धारा, जो इस क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित करती है। 'पद्म पुराण' में इसकी तुलना साक्षात सूर्य से करते हुए कहा गया है कि जहां सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम होता है, वहां स्नान करने वाले ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। यह यज्ञ की महिमा ही है, जिसके कारण मान लिया गया है, कि जो प्रयाग की धरती पर पैर भी धर लेता है, उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रयाग में लगभग 70 हजार तीर्थ उपस्थित हैं। पद्म पुराण के अनुसार अपने घर में मृत्युशय्या पर पड़ा व्यक्ति भी, यदि दूर भी रहते प्रयाग का नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मलोक का भागी होता है। 'मत्स्य पुराण' में कहा गया है कि युग चक्र पूर्ण होने पर जब रुद्र (शिव) पृथ्वी का विनाश करते हैं, प्रयाग तब भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि विष्णु वेणीमाधव, शिव अक्षय वटवृक्ष के रूप में और स्वयं ब्रह्मा छत्र में उपस्थित रहते हैं। शूलपाणि स्वयं वट की रक्षा करते हैं और यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले को सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संगम की मिट्टी का भी अपने शरीर पर स्पर्श करा लेता है, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और गंगा स्नान के बाद स्वर्ग के पुण्य का भागीदार बन जाता है। यहां यदि किसी को मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह जन्म और मृत्यु के सांसारिक चक्र के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कुंभ मेला लाखों- करोड़ों लोगों को एक साथ आने का अवसर देता है। यहां विभिन्न साधु-संत, नागा साधु और अन्य धार्मिक गुरुओं के दर्शन होते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहां विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से लोग आते हैं, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। मेले में लोक नृत्य, संगीत, कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है, जो इसे एक रंगीन उत्सव बनाता है। अगर धर्म-कर्म से हटकर बात करें तो कुंभ मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहां सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ आते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं। यह एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में सिखों ने भी स्नान किया। इसमें आने वाले लोग कई तरह के त्याग और अनुशासन का पालन करते हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं, जमीन पर सोते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। यह उन्हें अपने अंदर की शांति और संयम को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप आएंगे तो कुंभ मेला हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हिन्दू संस्कृति की विविधता और गहराई को दर्शाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय संयोग इस मेले को और भी खास बना देता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और शांतिपूर्ण जमावड़ा होगा, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह मेला आत्म-खोज का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इसलिए भी आते हैं।

(लेखक पूर्व सांसद व स्तंभकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

मुंह के मौन से ज्यादा ज़रूरी 'मन का मौन'

संकलित
दर्शन

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहें, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि 'अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।' अर्थात 'मन का मौन' करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए 'कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।' हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

भरे गिलास से मंदिर की परिक्रमा

संकलित
प्रेरणा

एक महिला रोज मंदिर जाती थी एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा अब मैं मंदिर नही आया करूँगी इस पर पुजारी ने पूछा क्यो? तब महिला बोली: मैं देखती हूं लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं कुछ ने तो मंदिर को ही गपसप करने का स्थान चुन रखा है, कुछ पूजा कम पाखंड ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे फिर कहा: सही है! परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से कुछ कर सकती है। महिला बोली: आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा: एक गिलास पानी से भरकर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए शर्त ये है कि गिलास का पानी गिरना नही चाहिए। महिला बोली: मैं ऐसा कर सकती हूँ फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे: 1) क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? 2) क्या आपने किसी को मंदिर में गपसप करते देखा? 3) क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली: नही मैंने कुछ भी नही देखा। फिर पुजारी बोले: जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इस में से पानी न गिर जाए इसलिए आपको कुछ दिखाई नही दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परम पिता परमात्मा में ही लगाना फिर आपको कुछ दिखाई ही नही देगा। सिर्फ भगवान ही सर्वत्रत दिखाई देगा, जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा।

कुंभ

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के दौरान सोमवार को लोग एक लाख साधु से शास्त्रार्थ करते हुए।

आज की पाती

शादियों में दिखावा, गरीबों के लिए मुसीबत

हमारे देश में लोगों में दिखावे की भावना बहुत बढ़ गई है। लगभग हर त्योहार, सामाजिक और धार्मिक समारोहों में भी दिखावा किया जा रहा है। यह दिखावा हमारा आर्थिक नुकसान ही नहीं करवाता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी भंग करता है, खास तौर पर उनके लिए यह दिखावा मुसीबत बनता है जो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। त्योहारों के साथ-साथ अब शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। हमारे देश में शादी समारोह में भी फिजूलखर्ची लोक दिखावे के लिए होने लगी है। लोक दिखावे के लिए लोग अपने पैर चादर से बाहर भी पसार देते हैं। इसके कारण अनेक समस्याएं, गरीबों के सामने पैदा होती हैं। दिखावे की बढ़ती परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। - महेश यादव, पलवरी

ट्रेंड

औपनिवेशिकता से मुक्त हों

यह हस्यास्पद बात है कि अड़ानी अपने सहयोगी पूंजीपतियों से हमें लगातार सीख के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते रहे हैं। देश के इतिहास का पहला महत्तम उपनिवेशवादियों के विरुद्ध पूंजीपतियों के साथ से अदा था। हमें खुद को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करना होगा। -जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

मनरेगा में यूपी प्रथम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिन रोजगार देने में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। मनरेगा को सफलता हासिल की बना रही है। -केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी

एआई का लोकतंत्रीकरण

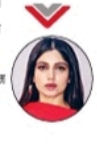

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शिक्षा विभाग का लोकतांत्रीकरण करने, शिक्षा पर आधारित शिक्षकों को बढ़ावा देने और बच्चाओं वर्गों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा उद्योग में सुधार करने की क्षमता है। शिक्षा आर्थिक लाभ कराना या प्लेटफॉर्म है। -मुनि पेडनेकर, अभिनेत्री

परिवार व दर्शकों को श्रेय

किंग बॉस-10 का विजेता बनने के लिए मैं अपने फैंसेज से लेकर अपनी मां, बहन, भाभी, मित्र तक और दोस्तों, प्रशंसकों को इसका श्रेय देना चाहूंगा। मेरे लिए यह बड़ी उपलब्धि है। -पंकजवीर मेहरा, अभिनेता

करंट अफेयर

भारतीय समुदाय से जुड़े संगठन की ट्रंप को बधाई

वैश्विक भारतीय समुदाय की गैर-लाभकारी संस्था 'इंडियास्पोरा' ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए प्रशासन के तहत अमेरिका-भारत संबंध और प्रगाढ़ होंगे। 'इंडियास्पोरा' के संस्थापक-अध्यक्ष एमआर रंगास्वामी ने कहा, 'इंडियास्पोरा और भारतीय-अमेरिकी समुदाय की ओर से मैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में नए राजनीतिक माहौल में अमेरिका-भारत संबंध और प्रगाढ़ होंगे।' रंगास्वामी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों पक्षों के शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने मजबूत संबंध स्थापित किए और इस अहम द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में मजबूत द्विदलीय समर्थन है।' अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने नागरिक अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कई भारतीय-अमेरिकियों को नियुक्त किया है। इनमें हरमीत कौर ढिल्लों, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, जय भट्टाचार्य और श्रीराम कृष्णन प्रमुख हैं। कार्यवाहरी निदेशक संजीव ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में इंडियास्पोरा का ध्यान दो प्रमुख क्षेत्रों में रहा है-प्रवासी भारतीयों की नागरिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना तथा अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना।'

ऑफ बीट

गर्मी से थकान और लू लगने में क्या अंतर है?

गर्मी से संबंधित बीमारियां हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं। वे अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से होती हैं, चाहे वह गर्म परिस्थितियों, शारीरिक परिश्रम या दोनों से हो। सबसे आम बीमारियों में शामिल हैं: गर्मी से शोथ: हाथ, पैर और टखनों में सूजन। मांसपेशियों में दर्द-ऐंठन: अनैच्छिक पैठन जो आमतौर पर व्यायाम के बाद होती है।अधिक गर्मी के कारण बेहोशी तक आ जाती है। यह तब होता है जब शरीर अत्यधिक परसीने के कारण पानी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। (लेकिन फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस से कम)। इसके लक्षणों में सुस्ती, कमजोरी और चक्कर आना शामिल है, लेकिन चेतना या मानसिक स्पष्टता में कोई अंतर नहीं आता। लू लगना (तापघात): जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो यह एक चिकित्सकीय आपातस्थिति होती है। इससे तंत्रिका तंत्र से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे भ्रम, दौरे और बेहोशी, जिसमें कोमा भी शामिल है, फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। लू लगने और गर्मी से थकान के कुछ लक्षण एक जैसे होते हैं। इससे चिकित्सा पेशेवरों के लिए भी अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 21 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे
-विलियम जेम्स

चौकसी जरूरी

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भीषण आग लगना चिंता की बात है। शुक्र है कि अखाड़े वालों व दमकलकर्मियों ने फौरन आग पर काबू पा लिया। एकदिन पहले भी इसी तरह आग लगी थी। आग सेक्टर 19 में शास्त्री पुल के नीचे लगी। 25 में से 20 टेंट व ढेरों फूस की झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। कहा गया कि खाना पकाते समय आग लगी, जिसमें तीन कुकिंग सिलेंडरों के ब्लास्ट से श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पूरे महाकुंभ मेले में एलर्ट जारी कर दिया गया। दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में देरी का कारण भीड़ बताया जा रहा है। हालांकि कोई जन हानि नहीं हुई है। मगर वर्षों से दहशत जरूर फैल गई। आग की विकराल लपटें दारागंज-झूंसी के बीच बने नये ट्रेनपुल के करीब पहुंच गईं। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को रोकने में नाकाम रेलवे ने

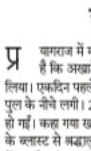

उसे निकालने के बाद प्रयागराज-वाराणसी रेलमार्ग पर आने-जाने वाली तमाम ट्रेनों की आवा-जाही रोकी गई। उप्र के मुख्यमंत्री प्रयागराज में ही मौजूद थे, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। भारी भीड़ को संभालना निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। ये टेंट निजी कंपनी द्वारा लगवाए गए हैं। मगर बता रहे हैं, इनके भीतर आग जलाने की बात उक्त कंपनी से नहीं की गई थी। 144 बाद के पड़ने वाले इस महाकुंभ का विशेष महत्व है। जिसे देखते हुए मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी को भारी भीड़ पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना टेढ़ी खीर हो सकती है। पिछले यानी 2013 के कुंभ के दरम्यान तीन दर्जन श्रद्धालु भगदड़ में मारे जाने जैसी घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है। मुफ्त भोजन व भंडारों के बावजूद श्रद्धालु अपनी खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। ठिठुरा देने वाली सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाये जाते हैं। बीड़ी-सिगरेट, चिलम पर पाबंदी मुश्किल है। ऐसे में गैस सिलेंडर लाने, स्टोव या चूल्हा जलाने वालों को रोका जाना और भी दुष्कर है। भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाये रखना बड़ी चुनौती है, परंतु उससे भी बड़ी दिक्कत अपने यहां अतिविशिष्टों की सुरक्षा-व्यवस्था में जुटना भी कम नहीं है। सुरक्षातंत्र का बड़ा अमला वीआईपी स्नान में इतना व्यस्त हो जाता है कि आम जनता से ध्यान भंग होना लाजमी है। जनता में भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इतने बड़े आयोजन में ज्वलनशील सामग्री को सुरक्षित रखना नामुमकिन है। फिर भी दमकल विभाग को विशेषाधिकारों द्वारा चौकस बनाए जाने की जरूरत है।

तेजस्वी पर भरोसा

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की कमान अब पूरी तरह तेजस्वी यादव के कंधों पर होगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में यह तय हुआ कि तेजस्वी यादव पार्टी चलाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे, लेकिन अब पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार भी अब तेजस्वी के पास होगा, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता था। लाजिमी है कि एक तरफ पार्टी में तेजस्वी युग का आगाज हो गया तो दूसरी ओर लालू परिवार में भी 'सियासत' शुरू होने की आशंका है। क्योंकि मीसा यादव और रोहिणी भी राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि तेजप्रताप भी मां राबड़ी के ज्यादा करीब हैं और अपने बयान के जरिये सुर्खियों में रहते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से तेजस्वी ही पार्टी का कामकाज देख रहे थे, लेकिन चुनाव के समय लालू यादव

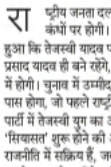

की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। अब यह जिम्मेदारी भी तेजस्वी के कंधों पर होगी। तेजस्वी युवा हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के अलावा इस बार के लोक सभा चुनाव में उनकी मेहनत का हर कोई कायल रहा। हालांकि उनकी मेहनत चुनाव परिणाम में परिलक्षित नहीं हुई, मगर उन पर जनता और पार्टी का भरोसा पूरी मजबूती के साथ है; यह जरूर दिखा। खास बात यह है कि तेजस्वी काफी ऊर्जावान हैं और पिता लालू प्रसाद से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। बाकी परिवार के सदस्यों की बात करें तो मीसा इस बार भले पाटलिपुत्र से सांसद बनी मगर बिहार की राजनीति को समझता से समझाने का काम तेजस्वी के अलावा न तो रोहिणी ने किया और न तेजप्रताप ने। हां, राबड़ी देवी की भूमिका भी अब पार्टी में काफी सीमित हो गई है। स्वाभाविक है, लालू ने दांव तेजस्वी पर चला है और एक तरह से अध्यक्ष का पद अपने पास रखकर यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि तेजस्वी के कामकाज पर उनकी नजर रहेगी। इस बात में कोई शक नहीं कि युवा तबके में तेजस्वी की स्वीकार्यता है। साथ ही यादव मतदाता और मुस्लिम समुदाय भी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ जद (यू)-भाजपा की सरकार की खामियों को सामने लाना उनके लिए सबसे कठिन होगा। हां, अगर वो नीतीश सरकार की नाक में दम करेंगे तो हो सकता है, अगली सरकार के मुखिया वही होंगे।

रेवड़ी कल्चर/नीरज शर्मा 'भरथल'

वायदों का बाजार है चुनाव

लगता है पूरा देश ही वायदों पर चल रहा है। हर चुनाव से पहले लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं। एक पार्टी कुछ वायदा करती है दूसरी पार्टी उस से भी बड़ा वायदा कर देती, तीसरी पार्टी और दो-तीन चीजें बीच में बढ़ा देती है। वायदे चुनावों में किए जाते हैं, फिर भूला दिए जाते हैं। जो पार्टी दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के वायदों का यह कह कर विरोध कर रही थी कि पैसा कहां से आएगा, अपनी घोषणाओं से पहले पूरे आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी कि दिल्ली के खजाने में इतना पैसा ही नहीं है, अब वही पार्टी अपने विरोधी से बड़े वायदे कर रही है। उन्हें भी पता है और जनता को भी पता है कि वायदे तो बस वायदे हैं।

चुनाव के बाद वही वायदे चुनावी जुमले करार दे दिए जाएंगे। अगर इन वायदों में कुछ दम होता तो आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी मूल मुद्दों में शामिल नहीं होते। जनता हर बार ऐसे वायदों को सुनती है और चुनाव के बाद इन वायदों के लालच में चुनी सरकार के कार्यों को देख अपना माथा पीटती है। आज चुनावों में बड़ी-बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पर देकर टिकट लेकर आते हैं, अब सोचने की बात यह है जो प्रत्याशी इतना पैसा खर्च टिकट ला रहा है वो जनता से किए वायदे पूरे करने के लिए जोर लगाएगा या अपनी 'इंवेस्टमेंट' को प्रॉफिट सहित निकालने की सोचेगा। जिस उम्मीदवार को जनता जिताकर भेजती है वही चुनाव जीतने के बाद जनता को अगूंठा दिखा वायदों को जुमला बता अपना पिंड छुटा लेता है। असल में जनता को यह चाहिए चुनावों के दौरान उम्मीदवारों से उनके और उनकी पार्टी के नए वायदों को एक तरफ रख पुराने वायदों के बारे में पूछे की उनका क्या हुआ? परंतु असल हालत यह है कि जनता भी जानती है कि यह वायदों का बाजार सिर्फ चुनावों में ही गर्म होता है। वोटों के बाद इनके पूरा होने की उम्मीद बबूल से आम की उम्मीद करने जैसा है। कुल मिलाकर, जनता सब समझती है पर बोलती कुछ नहीं, जिस दिन जनता बोलने लग गई और नेता से उनके वायदों पर सवाल पूछने लग गई। उस दिन इन वायदों के बाजार पर ताला लगने में देर नहीं लगेगी।

रणनीतिक सूझ दिखाए भारत

पिछले साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जब पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच समझौते की खबर आई तो एकबारगी लगा कि एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और परमाणु सशस्त्र सेनाओं के बीच संबंध सामान्य हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' वाली नरमी लौटने से एक उम्मीद जगी थी कि एशियाई रिजन तनाव व संघर्ष के वातावरण से मुक्त हो सकेगा। दुर्भाग्य से पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों के बीच विश्वास बहाली की जमीन पुख्ता हो पाती इससे पहले ही चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर विवाद को हवा दे दी। चीन के इस निर्णय से भारत सकते में है।

भारत का मानना है कि चीन के इस प्रोजेक्ट से निचले बहाव वाले देशों खासकर भारत और बांग्लादेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। उसने चीन सरकार को दो टूक कहा है कि किसी भी तरह के निर्माण से पहले निचले बहाव वाले देशों के हितों का ध्यान रखा जाए। भारत का मानना है कि बांध का निर्माण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षति और निचले इलाकों में जल संकट उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, चीन ने योजना का बचाव करते हुए कहा है कि दावों के अध्ययन के बाद सुरक्षा मुद्दों का समाधान किया गया है, इसलिए बांध के निर्माण से दूसरे देशों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि चीन की कथनी और करनी पर किस हद तक भरोसा किया जाए। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने परियोजना पर सवाल खड़े किए हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के पूर्व की ओर से निकलती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए यह बांग्लादेश तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो है। तिब्बत में इसका बहाव क्षेत्र 1625 किमी है। भारत में इसकी लंबाई 918 किमी है। यहां इसे सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नदी का

चीन ने बनाया वाटर बम

डॉ. एन.के. सोमानी

बाकी 337 किमी का हिस्सा बांग्लादेश में है, जहां इसे 'जमुना कोयला' कहा जाता है। तीन देशों में बहाव क्षेत्र होने के कारण नदी पर शुरू की जाने वाली किसी भी परियोजना या एक तरफा तौर पर होने वाले निर्माण पर सवाल उठने लगते है। पिछले 25 दिसम्बर को जब चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण की घोषणा की खबरें मीडिया में आई तो भारत सरकार हरकत में आई।

दरअसल, चीन जिस तरह से अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का उपयोग प्रतिद्वंद्वी देशों को आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर घेरने के लिए करता है उससे भारत की चिंता बढ़नी

ही थी। चिंता के कई बड़े कारण है। पहला, इस परियोजना के शुरू होने के बाद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर हमेशा चीनी दखल का खतरा मंडराता रहेगा। दूसरा, चीन का भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर तीनों देशों के दावे को लेकर विवाद है। तीसरा, भारत-चीन संबंधों में तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में चीन इस डैम को भारत के साथ सौदेबाजी का जरिया बना सकता है। चौथा, चीन इस डैम का उपयोग 'वाटर बम' के तौर पर भी कर सकता है।

तनाव और विवाद की स्थिति में चीन इस डैम के जरिए भारत के सीमाई इलाकों में बड़ी मात्रा में वाटर फ्लो करके बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देगा। सच तो यह है कि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और असम की जीवन रेखा है, जो पांच करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल, सिंचाई और जलविद्युत के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ऐसे में अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण करता है तो पानी के बहाव पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। परिणामस्वरूप वह शुष्क मौसम के दौरान पानी के प्रवाह को कम कर कृषि और पेयजल के लिए जल संकट उत्पन्न करने में संकोच नहीं करेगा। दूसरी ओर मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी छोड़ने का भी खतरा बना रहेगा। इससे पहले भी चीनी अपस्ट्रीम गतिविधियों के कारण असम, अरुणाचल और हिमाचल में बाढ़ आ गई थी। दरअसल, चीन अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनाए रखता है। निर्माण योजना को लेकर पड़ोसी देशों के बीच भ्रम बनाए रखना और महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी साझा करने से बचना उसकी इसी 'निर्माण नीति' का हिस्सा है। साल 2010 में कई वर्षों के इनकार के बाद उसने स्वीकार किया कि वह ब्रह्मपुत्र पर जंगमु बांध बना रहा है।

हालांकि, भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नदी के पानी को लेकर विवाद है लेकिन दोनों देशों के साथ संधि होने के कारण इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है परन्तु चीन के साथ भारत की कोई संधि नहीं है दोनों के बीच केवल एक समझौता ज्ञापन है जिसके तहत चीन केवल ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करता है। यह एक अस्थायी समझौता है जिसकी हर पांच साल में समीक्षा की जाती है और चीन जब चाहे इससे पीछे हट सकता है। सवाल है भारत चीन की इस चुनौती से निबटने के लिए क्या कर सकता है। पूरे मामले में सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू यह है कि भारत को इस प्रोजेक्ट की समय रहते खबर क्यों नहीं लगी? दूसरा जिस तरह से भारत ने एक सप्ताह से अधिक का समय बीतने के बाद चीन के समक्ष आपत्ती प्रकट की उस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

खैर! अब भी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। चीन की चुनौती से निबटने के लिए भारत ने रणनीतिक उपायों के साथ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आगे बढ़ने के संकेत दिए। हालांकि, भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर डैम का निर्माण कर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से 2023 की शुरुआत में भारत ने रणनीतिक चतुराई के साथ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करके ग्लोबल साउथ की दौड़ से चीन को अलग किया है, वैसी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय मौजूदा चुनौती से निबटने में देना होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

हालांकि, भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर डैम का निर्माण कर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से 2023 की शुरुआत में भारत ने रणनीतिक चतुराई के साथ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करके ग्लोबल साउथ की दौड़ से चीन को अलग किया है, वैसी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय मौजूदा चुनौती से निबटने में देना होगा।

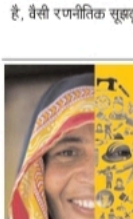

अपने कौशल को लेकर भारतीय महिलाएं अधिक 'सजग'

- भारत में पुरुष कामगारों की तुलना में ऐसी महिला कर्मियों की संख्या अधिक है जो करियर में उन्नति के लिए अपने कौशल को लेकर आश्वस्त हैं
- एडीपी रिसर्च की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। एडीपी की मुख्य अर्थशास्त्री नेला रिचर्डसन ने कहा, हमारी रिसर्च से पता चला है कि कंपनियां तकनीकी प्रगति से लाभ उठाना चाहती हैं, तो उन्हें अपने कामगारों के कौशल और करियर ग्रोथ में निवेश करना चाहिए

फोटो : मीडिया इन्फ्यूज़न)

मैं उस घोषित इमरजेंसी का घनघोर निंदक था। आज भी हूं। कल रात 'इमरजेंसी' यह सोचकर देखने गया कि फिल्म को फिल्म की तरह देखूंगा, लेकिन वह सरासर वेड़ीमार फिल्म निकली। कंगना रनौत की अपनी राजनीतिक भड़ास। हां, पहले ही बता दूं कि हॉल लगभग खाली था, हमारे आगे तो निपट खाली।

ओम थानवी, पत्रकार
@omthanvi

बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता जरूरी

मुद्दा | **अमित बैजनाथ गर्ग**

हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में ग्लोबल हेल्थ स्पैन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर वक्ताओं ने खुलकर चर्चा की। सम्मेलन में सबसे अहम बात बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता के रूप में उभरकर सामने आई। सम्मेलन में करीब दो हजार से अधिक वैज्ञानिक, उद्यमी, नीति निर्माता और विचारक एकत्रित हुए। उन्होंने बुजुर्ग होते समाज के भविष्य के समक्ष आने वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर गहनता से चर्चा की। उनका कहना है कि दुनिया में स्वस्थ वृद्धावस्था के अप्रयुक्त अवसरों के साथ-साथ उभरते हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी, नीतिगत परिवर्तन और भविष्य के लिए आवश्यक निवेश पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। सम्मेलन में यह बात भी सामने आई कि आज वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा 73.4 वर्ष है, जिसके बढ़कर सौ साल होने की उम्मीद की जा सकती है।

वक्ताओं ने कहा कि जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद हमारे जीवन के अंतिम वर्ष अक्सर दीर्घकालिक बीमारी में गुजर रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ कई पूर्वाग्रह और बुढ़ापे को सामाजिक और आर्थिक बोझ के रूप में पेश करने की कहानी सामने आ रही है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जॉन आर. बिर्यर ने कहा कि कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्ध आश्रितों की संख्या का अनुपात नकारात्मक धारणाओं को मजबूत करता है और समाज में वृद्ध वयस्कों के सार्थक योगदान को नजरअंदाज करता है। अमेरिका और यूरोप में वृद्ध वयस्क भुगतान किए गए काम, स्वयं सेवा और देखभाल के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित सात फीसद योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्ध आबादी आर्थिक स्थिरता और नवाचार के लिए भी एक अप्रयुक्त शक्ति हो सकती है। अमेरिका में 50 से अधिक उम्र के उद्यमियों की संख्या साल 2007 के मुकाबले साल 2024 में दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जीने से हमें रिटायरमेंट शब्द से भी रिटायर होना पड़ सकता है। अनुमानित जीवनकाल शताब्दी के करीब पहुंचने के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा कामकाजी जीवन अतिरिक्त 20-40 वर्षों तक बढ़ जाएगा। यह शिक्षा और काम के बारे में हमारी सोच को फिर से परिभाषित करेगा। वहीं कार्यबल में बने रहने के कारण अर्थशास्त्र से परे भी है। इस बात के बढ़ते प्रमाण हैं कि

सेवानिवृत्ति के बाद काम करने से हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। साथ ही मानसिक प्रगति और सामाजिक जुड़ाव भी मिलता है। उन्होंने कहा कि वृद्ध लोगों को समाज के मूल्यवान सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए नकारात्मक रूढ़िवादिता को समाप्त करना होगा तथा लंबी आयु के लाभों के बारे में सार्वजनिक धारणा को व्यक्तियों, समाजों और अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवा की लागत का बड़ा हिस्सा उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से प्रेरित है। फिर भी उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य अवधि विज्ञान को बहुत कम धन उपलब्ध है। अमेरिका अल्जाइमर रोग के इलाज पर सालाना लगभग 305 बिलियन डॉलर खर्च करता है। यह आंकड़ा 2050 तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। यूएस रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का अनुमान है कि हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण देश को स्वास्थ्य सेवा व्यय और उत्पादकता हानि के रूप में प्रतिवर्ष 363 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। मधुमेह के कारण अनुमानित वार्षिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ 327 बिलियन डॉलर है, जबकि गठिया और संबंधित बीमारियों के कारण होने वाला खर्च 303 बिलियन डॉलर से अधिक है। वहीं देश वृद्धावस्था के लक्षणों के उपचार पर अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के वार्षिक अनुसंधान बजट का एक प्रतिशत से भी कम या 337 मिलियन डॉलर वृद्धावस्था के जैव विज्ञान को समझने में खर्च होता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि उम्र बढ़ने के मूल कारणों को संबोधित करने से व्यक्तिगत बीमारियों को लक्षित करने की तुलना में निवेश पर अधिक लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि विश्व की जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है तथा अनुमान है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। वहीं देरी से कार्रवाई करने पर जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी और अतिरिक्त वर्ष अस्वस्थता में गुजारने पड़ेंगे, जबकि युवा लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी होगी। वृद्ध होते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा वृद्धावस्था के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाले नीतिगत समायोजन, रोकथाम और निवेश को प्राथमिकता देने वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां तथा समस्त मानवता को लाभ पहुंचाने की क्षमता रखने वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के वैश्विक सहयोग के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

परमात्मा | **ओशो**

लोग मेरे पास आते हैं, और वह कहते हैं: 'हम परमात्मा को जानना चाहते हैं-परमात्मा कहां हैं?' अब यह प्रश्न ही अर्थ हीन है? वह कहां नहीं है? तुम पूछते हो कि वह कहां है, तुम्हें विल्कुल ही अंधा होना

चाहिए। क्या तुम उसे देखा नहीं सकते हो? केवल वही तो है, वृक्षों में, पक्षियों में, पशुओं में, पहाड़ों में, जल में, नव में, सब जगह वही तो है। एक स्त्री में एक पुरुष में, पिता में माता में, बेटे में कहां नहीं है। उसी ने तो इतने सारे रूप ले लिए है। हर तरफ वही तो है। वह हर जगह से तुम्हें पुकार रहा है, और तुम सुनते ही नहीं हो। तुमने अपनी आंखें हर तरफ से बंद कर ली है। तुमने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली है। तुम क्या किसी और देखते ही नहीं हो। तुम एक बहुत ही संकरे ढंग से, बड़े ही केंद्रीभूत तरीके से जी रहे हो। यदि तुम धन की और देख रहे होते हो, तुम वस धन की तरफ देखते हो; फिर तुम किसी और तरफ नहीं देखते हो। यदि तुम शक्ति की तलाश में होते हो, तुम केवल शक्ति की और ही देखते हो, तुम किसी और तरफ नहीं देखते। और स्मरण रखना : धन में परमात्मा नहीं है-क्योंकि धन तो मनुष्य निर्मित है, और परमात्मा तो मनुष्य निर्मित हो ही नहीं सकता। जब मैं कहता हूं कि परमात्मा हर जगह है, स्मरण रखना कि उन चीजों को, जिन्हें मनुष्य ने निर्मित किया है, इसमें शामिल नहीं करना है। परमात्मा मनुष्य-निर्मित नहीं हो सकता। परमात्मा धन में नहीं है। धन तो मनुष्य का एक बड़ी चालाकी भरा आविष्कार है। और ईश्वर शक्ति में भी नहीं है, वह भी मनुष्य का एक पागलपन है। किसी पर अधिपत्य जमाने का विचार ही विक्षिप्त है। यह विचार ही कि 'मैं सत्ता में रहूं और दूसरे सत्ता-विहीन रहे,' एक पागल आदमी का विचार है, एक विनष्टकारी विचार है। परमात्मा राजनीति में नहीं है और परमात्मा धन में भी नहीं है। न ही परमात्मा महत्त्वाकांक्षा में ही है, लेकिन परमात्मा हर उस चीज में है, जहां मनुष्य ने उसे नष्ट नहीं किया। जहां मनुष्य ने कोई अपनी ही रचना नहीं की है। आधुनिक जगत में यह सर्वाधिक कठिन बातों में से एक है। क्योंकि चारों तरफ से तुम इतनी मनुष्य-निर्मित चीजों से घिरे हुए हो। क्या तुम वस इस तथ्य को देख नहीं पाते? जब तुम एक वृक्ष के समीप बैठे होते हो, परमात्मा को महसूस करना आसान है। जब तुम कोलतार की बनी सड़क पर बैठे होते हो, तुम उस कोलतार की सड़क पर परमात्मा को वहां न पाओगे। यह बहुत सरल है।

रीडर्स मेल

देश विरोधी न्यूज चैनल

तथाकथित सबसे तेज एवं सबसे अलग कहे जाने वाले टीवी चैनलों का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पता चला की हर रोज पिछले दस बारह बरसों से, हिन्दू-मुसलमान और हिन्दुस्तान पाकिस्तान का नाम लेकर डिबेट में हिस्सा लेने वाले भाजपाई एवं उग्र राष्ट्रवाद के चिंतक, जो शुकीकरण का खाई खोद रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ छद्म राष्ट्रवादी राजनीति ही नहीं है बल्कि वो तमाम मीडिया भी है जो आज इस देश को धार्मिक कट्टरता के दलदल में धकेल रहा है। 16 जनवरी को एक कार्यक्रम में प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने बताया की 'फोन पर न्यूज एंकर ने कहा कि आप बहुत शांत रहते हैं। आपको पैनेलस्ट से लड़ना है। शो हिट जाएगा। आप भी ट्रेंड करेंगे हम भी ट्रेंड करेंगे। आपको मुसलमानों की टोपी-दाढ़ी के बारे में कहना है।' कैसे मीडिया वाले देश का एकता अखंडता को दरकिनार करके नफरत को परोसने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रो. सिन्हा को अब उस तथाकथित एंकर और चैनल का नाम भी सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि उस आधार पर उस चैनल के ऊपर न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो बल्कि उसे एंकर, संपादक एवं प्रबंधक को गिरफ्तार करके चैनल को बंद करवाने की कार्रवाई हो।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सोशल मीडिया पर संभल कर

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभावी है। यौनिकता भी इससे अछूती नहीं रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने न केवल विचारों के आदान-प्रदान का तरीका बदला है, बल्कि यौनिकता के बारे में हमारे दृष्टिकोणों को भी प्रभावित किया है। जहां एक ओर सोशल मीडिया ने यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा का माहौल तैयार किया है, वहीं दूसरी ओर इसने कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर यौनिक पहचान, समलैंगिकता, और लैंगिक समानता पर चर्चा बढ़ी है, जो समाज में स्वीकृति और समझ बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। हालांकि, सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अक्सर यौनिकता को एक भौतिक आकर्षण या दिखावे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो युवा मानसिकता पर दबाव डालता है। इस प्रकार, सोशल मीडिया और यौनिकता का आपसी संबंध जटिल है। जहां एक ओर यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसका गलत उपयोग भी हानिकारक हो सकता है।

चंदन कुमार नाथ, चरपेठा, असम

ट्रंप के बाद कैसा परिदृश्य

हाल ही में जो बाइडन के राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा उनकी स्थायी विरासत पर बड़ी चिंताएं पैदा करती है। क्या उनकी सरकार वास्तव में 'भारत समर्थक' थी, या वह केवल मौजूदा संबंधों का लाभ उठा रही थी? बाइडन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अंतर्निहित विभाजनों को कैसे सुलझाएगी? इसके अलावा, क्या ट्रंप की वापसी अमेरिकी विदेश नीति को बदल सकती है, खासकर भारत के प्रति। बाइडन के दुखद प्रस्थान से भविष्य के नेतृत्व के लिए कौन से विषय सीखे जा सकते हैं, जो पूरे अमेरिका में तीव्र रूप से विभाजित हैं?

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा प्रेस कम्पनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंहा* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-33, अंक 155 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कलापूर्ण सामग्री के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 289

दावोस में भारतीय राज्य

घरेलू निजी निवेश की कमजोरी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में धीमी गति से हो रही वृद्धि के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने दावोस के स्विस स्की रिजॉर्ट में आयोजित हो रही विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में कामयाबी का हरसंभव प्रयास आरंभ कर दिया है। वहां हमारे देश के दो पविलियन होंगे। एक केंद्र सरकार के लिए और दूसरा छह राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए जिनमें तीन मुख्यमंत्री शामिल हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं जिनके पास रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम मंत्रालय हैं। उनका कहना है कि उनकी योजना देश के समावेशी वृद्धि के एजेंडे को प्रचारित करने की है। दावोस में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी वहां विदेशी निवेशकों को अपने-अपने प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास करने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दावोस भारत के लिए बहुत मायने रखता है।

उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश वहां 15 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। नायडू वहां 19 बैठकों में शामिल होंगे और प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 50 बैठकों में शामिल होंगे। लगभग सभी राज्यों ने अपनी-अपनी पहलों की ब्रांडिंग की है। उदाहरण के लिए 'बुलिश ऑन टीएन', 'तेलंगाना राइजिंग 2050' आदि। यह बताता है कि मिशन कितना सक्रिय है और इस मान्यता की भी अपनी सीमाएं हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए भारी काम करना पड़ता है। परंतु इन प्रयासों की उपयोगिता पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि इनमें राज्यों के पदाधिकारियों को बहुत अधिक समय तथा धन व्यय करना होता है।

निस्संदेह दावोस को उन अवसरों के लिए जाना जाता है जो वहां परदे के पीछे उत्पन्न होते हैं। इसलिए संभव है कि भारतीय अधिकारियों के ये प्रयास उपयोगी नतीजे निकालने वाले हों। परंतु अन्य मुख्यमंत्रियों द्वारा इससे पहले के सालों में वहां की यात्रा बहुत अधिक सफल नहीं रही। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत को वहां अपेक्षित तरजीह नहीं मिलती। इस वर्ष जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है, हालात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए नायडू के बारे में खबर है कि वह वहां दो राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं, हालांकि उन नेताओं की पहचान अभी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही जिन विदेशी निवेशकों से संपर्क किया जा रहा है वे उचित ही यह पूछ सकते हैं कि आखिर घरेलू निवेशक अपने ही देश में निवेश करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। इसके बजाय दूसरे देशों में हो रहा भारतीयों का निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इनमें से हर राज्य, हर वर्ष निवेशक सम्मेलन आयोजित करता है जहां देश भर से निवेश प्रस्ताव आते हैं। वह निवेश शायद ही कभी जमीनी परियोजनाओं में फलीभूत होता हो।

विदेशी निवेशक इन बातों से भली भांति अवगत हैं। उन्हें भारत में कारोबारी सुगमता की राह की अनेक बाधाओं के बारे में भी पता है। इनमें नीतिगत अनिश्चितता से लेकर अधोसंरचना की समस्या तक शामिल हैं। महामारी के बाद उपभोक्ता मांग की अंग्रेजी के 'के' अक्षर जैसी प्रकृति भी एक बाधा रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में इनका यकीनन असर होगा। इन बातों के बावजूद जिन राज्यों ने दावोस में निवेश आकर्षित करने का निर्णय लिया है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अपवाद मान लिया जाए तो अन्य पांच राज्य देसी और विदेशी दोनों तरह के निवेश के मामले में आगे हैं। ऐसे में यह सवाल भी पैदा होता है कि अन्य उत्तरी राज्य जिन्हें खराब गुणवत्ता वाले रोजगारों से निजात पाने के लिए और अधिक विनिर्माण गतिविधियों की आवश्यकता है वे विदेशी निवेश जुटाने के ऐसे ही प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनकी अनुपस्थिति भी देश की एकांगी आर्थिक प्रगति के बारे में बहुत कुछ कह रही है।

वृहद आर्थिक नीतियों के समक्ष मौजूद चुनौतियां

प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक हालात के बीच सतर्कता एवं समझ-बूझ के साथ अर्थव्यवस्था में सुस्ती से निपटना वृहद आर्थिक नीति की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बता रहे हैं साजिद चिनॉय

वर्ष 2025 में वृहद आर्थिक मोर्चे पर भारत की प्राथमिकताएं पहले ही तय हो गई हैं। सबसे पहले, अमेरिका में तेज वृद्धि ने दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय हालात कठिन बना दिए हैं। चुनौतियों को धता बताने वाली अमेरिकी वृद्धि न केवल दूसरे देशों की वृद्धि से तेज है बल्कि इसने मुद्रास्फीति को घटाने का लाभ भी मुश्किल कर दिया है। पहले बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 2025 में पांच बार ब्याज दर घटाएगा मगर अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। इसलिए 10 साल में परिपक्व होने वाले अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड सितंबर से 100 आधार अंक बढ़ चुकी है और डॉलर सूचकांक भी 20 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने जा रहा है। डॉलर में मजबूती से तेजी से उभरते बाजारों की मुद्राएं दबाव में हैं और भारतीय रुपया भी अछूता नहीं रहा है।

दूसरी बात, डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से दुनिया में हालात और भी कठिन हो गए हैं। अमेरिका शुल्क लगाएगा तो वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ेंगी और वैश्विक पूंजीगत व्यय तथा वृद्धि उसी तरह घटेंगी, जैसा पहले व्यापार युद्ध के दौरान हुआ था। इससे डॉलर भी मजबूत होगा। इस बीच चीन पर सख्ती हुई तो वह अपनी अतिरिक्त क्षमता को भारत समेत दूसरे देशों में भेजेगा, जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण को खतरा हो जाएगा। सवाल यह है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका को कमजोर वैश्विक आर्थिक माहौल में भी तेजी से बढ़ाता रहेगा या सुस्त कर देगा। व्यापार में सख्ती हुई तो वैश्विक वृद्धि मंद होगी मगर राजकोषीय उदारता और नियमों में ढिलाई के कारण क्या अमेरिका इससे बचा रहेगा? उभरते बाजारों के लिए यह यानी कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि के साथ मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड सबसे बड़ी चुनौती होगी।

इधर पिछली कुछ तिमाहियों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर नरम पड़ गई है। निजी क्षेत्र में मांग के लिए शहरी खपत ही रीढ़ का काम करती थी मगर अब हालात बदल गए हैं। कोविड महामारी में हुई बचत लोग खपा चुके हैं। औपचारिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि धीमी हो गई है और उपभोग के लिए कर्ज देने में सख्ती बरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ तो रही है मगर रफ्तार धीमी है और कोविड महामारी के दौरान सरकार ने सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के जो उपाय किए थे उनकी सीमाएं भी आड़े आ रही हैं। निजी क्षेत्र मांग की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहा है और अगर चीन से अतिरिक्त माल भारत आने लगा तो उनका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए सुस्ती इस साल सरकारी व्यय में धीमी शुरुआत तक ही सीमित नहीं है।

भारत के लिए नीतिगत स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुनिया में कमजोर दिखे बगैर देश में आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे पहले, रुपया कमजोर बना रहे तो इसे संभालने के लिए ब्याज दरों का सहारा बिल्कुल नहीं लिया जाए। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए लचीली नीति तैयार करने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का मुख्य मकसद नीतिगत स्तर पर दो उपाय करना था। इनमें नीतिगत दरें और तरलता देसी वृद्धि तथा महंगाई की चाल को संभालती हैं और रुपया विदेश से आ रहे झटके झेलता है। रुपये में बड़ी उथल-पुथल रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की ढाल भी रहती है।

पिछले एक दशक से भारत के लिए यह रणनीति कारगर रही है। भारी विदेशी मुद्रा भंडार से भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति के स्तर पर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन पाई है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका में नीतिगत दरों के बीच फर्क बहुत कम हुआ है। इस बीच मुद्रास्फीति को साधने के प्रयासों को स्वीकार्यता तथा विश्वसनीयता मिलने से मौद्रिक नीति के भी हाथ खुल गए हैं। अब इस नीति को रुपया संभालने के लिए इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो जाएगा क्योंकि भारतीय और अमेरिकी बाजारों में कारोबारी दिशाएं काफी अलग हैं और देश में राजकोषीय उपायों की गुंजाइश कम रह गई है। साथ ही रुपये को जबरदस्ती ऊंचा रखा गया तो दुनिया में होड़ करने की क्षमता घटेगी, जिससे मौद्रिक हालात और सख्त हो सकते हैं।

इसके बजाय नीतिगत दरों और नकदी को देसी मुद्रास्फीति के अनुरूप किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति पर विनिमय दर का असर वहीं तक मायने रखता है, जहां इसमें उठापटक से मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कुछ राहत दिख रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं और खरीफ एवं रबी फसलों से इसमें और कमी आनी चाहिए। इसलिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर आने वाले महीनों में 4 प्रतिशत पर टिक सकती है। कमजोर रुपया इसमें इजाफा कर सकता है मगर वह मामूली होगा क्योंकि मांग पहले ही सुस्त है। इसलिए उत्पादन लागत बढ़ने की कुछ चोट कंपनियां खुद ही झेल लेंगी। इधर प्रमुख मुद्रास्फीति दर लगातार 3-4 प्रतिशत दायरे में बनी हुई है, जिससे लगता है कि अर्थव्यवस्था सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है। इन हालात में सुस्त होती वृद्धि दर को देखते हुए मौद्रिक नीति में मौजूद लचीलेपन का फायदा उठाकर नीतिगत दरों में धीरे-धीरे कमी हो और वृद्धि को सहारा मिले। मगर नरमी का फायदा तभी होगा, जब बैंकिंग तंत्र में नकदी की कमी (हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल के कारण) भी पूरी की जाए।

इस बीच रुपये को इसकी बुनियादी मजबूती के अनुरूप स्थिर होने दिया जाए और विदेशी मुद्रा भंडार का औचित्यपूर्ण इस्तेमाल हो किया जाए। इस समय डॉलर चढ़ रहा है और अमेरिकी शुल्कों के बाद चीन की मुद्रा युआन लुढ़क सकती है इसलिए रुपये को किसी खास स्तर पर रोकना न तो संभव है और न ही वांछनीय। रोकना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि विशाल विदेशी मुद्रा भंडार होने पर भी भारत को उसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा क्योंकि शुल्क की लड़ाई लंबी चल सकती है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रुपये की प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता घटी तो वृद्धि और सुस्त हो जाएगी। हम देख चुके हैं कि कमजोर रुपया भारत में आर्थिक गतिविधियां तेज करता है। इसके अलावा भारत पर अमेरिका ने शुल्क लगाए तो उनका असर कम करने के लिए रुपये में गिरावट ही सबसे उचित और सटीक प्रतिक्रिया होगी।

राजकोषीय नीति में गुंजाइश और भी कम है। पिछले दो साल में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक अंक में बढ़ा है, इसलिए सार्वजनिक ऋण एवं जीडीपी अनुपात फिर बढ़ना शुरू हो गया है। भावी झटकों के लिए राजकोषीय गुंजाइश तैयार करने के इरादे से पहले ऋण अनुपात स्थिर करना होगा और फिर इसमें कमी लानी होगी। इसके लिए खजाने को आने वाले वर्षों में आज से ज्यादा मजबूत बनाना जरूरी होगा। मगर यह भी जरूरी है कि राजस्व एवं व्यय में दिखने वाले अंतर को खजाने की मजबूती नहीं माना जाए। आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ने पर राजकोषीय मजबूती की गति भी धीमी ही हो ताकि राजकोषीय नीति वृद्धि के चक्र के मुताबिक बदलने वाली न बन जाए।

पहली नजर में तो दरें घटाना और राजकोषीय मजबूती की रफ्तार धीमी करना उन पुराने तरीकों से अलग है, जो ऐसे प्रतिकूल वैश्विक माहौल में अपनाए जाते हैं। मगर विदेशी मुद्रा भंडार और मौद्रिक ढांचा यहीं काम आते हैं। भारत में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां एक विश्वसनीय ढांचे के अंतर्गत काम करती रही हैं। इनकी मदद से हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की उम्मीदें को मजबूती मिली है और जोखिम कम हुए हैं। इनकी बदौलत नीति निर्धारकों को सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के दौरान संतुलन बनाए रखने में आसानी होती है।

बेशक वृद्धि के लिए असली दवा लगातार ढांचागत सुधार ही होते हैं। इनसे आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज होती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिनके फायदे बड़े वर्ग को मिलते हैं। भारत के लिए यह दौर अनोखा अवसर लेकर आया है। देश के बाहर की बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध हुआ तो कंपनियां कारोबार के लिए दूसरे सुरक्षित देशों की तलाश तेज कर देंगी। भारत को ऐसे मौकों का इंतजार करना चाहिए और इनका फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। देश के भीतर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें उसे अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और सुधारों को दोगुनी रफ्तार से लागू करने का मौका मिलेगा ताकि दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकें।

भारत का आर्थिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि संकट हमेशा इसके लिए नए अवसर लेकर आए हैं। व्यापार युद्ध होने, वैश्वीकरण का दायरा सिमटने और आर्थिक बाल्कनीकरण (बड़ी आर्थिक व्यवस्था टूटकर नई छोटी व्यवस्था बनना) से संबंधित अर्थव्यवस्था के सामने जो संकट पैदा होगा वह लंबा चलेगा और भारत को उसमें अपने लिए अवसर तलाशने का अवश्य प्रयास करना चाहिए।

(लेखक जे पी मॉर्गन में एशिया इकनॉमिक रिसर्च के प्रमुख हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

फैक्ट-चेकिंग सुविधा हटने से बिगड़ेंगे हालात

पिछले कुछ समय से 'एनरॉन एग' सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। मेज पर रखने लायक इस सफेद अंडे जैसे उपकरण को माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह 10 साल तक आपके घर को बिजली दे सकता है।

कहने की जरूरत नहीं कि यह पूरी तरह झूठ है। अमेरिका की ऊर्जा कंपनी एनरॉन के दिवालिया होने के बाद इसका नाम और प्रतीक चिह्न (लोगो) कंटेंट तैयार करने वाली किसी कंपनी ने खरीद लिया। यह कंपनी व्यंग्य, कटाक्ष भरी सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती है और खुद यह स्वीकार भी करती है। यह उपकरण नई एनरॉन के मुख्य कार्याधिकारी कॉनर गेडोस ने पेश किया था। गेडोस ने किसी के साथ मिलकर 'बर्ड्स आर नॉट रियल' किताब भी लिखी है। यह किताब ऑनलाइन चल रहे साजिश के सिद्धांतों का भंडाफोड़ करती है।

सबसे पहले तो इस उपकरण का नाम ही शक पैदा करता है क्योंकि एनरॉन की दिवालिया होने की प्रक्रिया बहुत चर्चा में रही थी। परमाणु ऊर्जा की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि 'एनरॉन एग' विशुद्ध रूप से विज्ञान कल्पना है और कुछ नहीं। तथ्यों की सत्यता जांचने वालों और ऐसी संस्थाओं (फैक्ट चेकर) ने भी यही बताया है तथा कई सोशल मीडिया यूजर इस पर चुटकुले और मीम भी बना चुके हैं। मगर हजारों लोग ऐसे भी थे, जिन्हें लगा कि यह बात बिल्कुल सच है। हो सकता है कि नई एनरॉन इसका फायदा उठाकर कमाई भी करने लगे।

'फर्जी खबरों' को फैलाने और बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने का सोशल मीडिया का यह अपना अंदाज है। इसमें हास्य-विनोद झलकता है और किसी को नुकसान भी नहीं होता। किसी ने महज भ्रम फैलाने के उद्देश्य से एक शिगूफा चला दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई तो उसे इसका फायदा भी मिलना चाहिए। मगर छह महीने पहले हमने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलने का नुकसानदेह पहलू भी देखा। 29 जुलाई को एक किशोर इंगलैंड के छोटे से शहर साउथपोर्ट में एक डांस क्लास के भीतर घुस गया और कई बच्चों को चाकू घोंप दिया। उनमें से तीन बच्चों की मौत भी हो गई।

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

हमला करने वाला यह किशोर एक्सेल रुडाकुबाना था। वह 17 साल का था, ब्रिटेन का नागरिक था और कार्डिफ में पैदा हुआ था। एक्सेल रवांडा मूल का था और ईसाई मत को मानता था। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

अमूमन नाबालिग अपराधियों के नाम और उनसे जुड़ी दूसरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। मगर इस घटना के बाद जो हिंसा हुई, उसे देखकर ब्रिटेन की सरकार को पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी। चरम दक्षिणपंथी धड़े से जुड़े लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि हमलावर मुस्लिम था और ब्रिटेन में शरण लेने आया था। सोशल मीडिया पर इन लोगों के भड़काऊ पोस्ट आने के बाद अगस्त में ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में जातीय दंगे भड़क उठे। एशियाई मुस्लिम समुदाय और उसके पूजा स्थलों को दंगाइयों ने निशाना बनाया।

कुछ दंगाई और दंगे भड़काने वाले लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सजा भी काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कुछ लोग साफ बचकर निकल भी गए।

इस पूरे मामले में हिंसा भड़काने वाले कुछ चरमपंथी लोगों को आर्थिक फायदा जरूर हुआ होगा। दंगे भड़कने के बाद पत्रकारों ने देखा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले चरम दक्षिणपंथी, नव-नाजी ब्रिटिश धड़े के कई लोगों को किस तरह कमाई होती है। इनमें कई लोगों की सोशल मीडिया एक्स के राजस्व साझेदारी मॉडल से कमाई होती है। एक्स 'पोस्ट लिखने वाले कुछ प्रमुख लोगों' को विज्ञापने से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा देती है।

मामला सीधा और साफ है। किसी पोस्ट पर लोगों की जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया आएंगी, जितने ज्यादा लोग उसे देखेंगे, उसे विज्ञापन से उतनी ही ज्यादा कमाई होने की संभावना बनेगी। ट्वीट जितना ज्यादा विवादित होगा उस पर प्रतिक्रिया या टीका-टिप्पणी आने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होंगी।

टॉमी रॉबिन्सन के नाम से पोस्ट लिखने वाले स्टीफन याजली-लेनन चरम दक्षिणपंथी 'इंगलिश डिफेंस लीग' चलाते हैं। उनकी संपत्ति 10 लाख स्टर्लिंग से अधिक है। रॉबिन्सन इस समय जेल में हैं और 18 महीने की सजा काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीरिया से आए 15 साल के एक शरणार्थी के बारे में भ्रामक पोस्ट नहीं डालने के आदेश का उल्लंघन किया था। एक्स उनके पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर हैं और फेसबुक पर भी उनके मुरीदों की संख्या कम नहीं है। उन्हें 2018 में ट्विटर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था मगर ईलॉन मस्क ने उनका खाता दोबारा चालू करा दिया। मस्क ने रॉबिन्सन को जेल से रिहा कराने के लिए अभियान भी चलाया था। रॉबिन्सन न केवल भ्रम और झूठ फैलाने वाली विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट से अच्छी-खासी कमाई भी की है।

अब इन दोनों उदाहरणों की आपस में तुलना सोशल मीडिया की खूबियों का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल के लिहाज से की जाए। आपको आभास होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी बनाम तथ्यों की जांच से जुड़ी मौजूदा बहस वास्तविक जीवन में क्या परिणाम ला सकती है।

भ्रामक खबरें फैलाने वाले फैक्ट चेकिंग की सुविधा बंद करने की मांग अक्सर इस दलील के साथ करते हैं कि इससे उनकी बोलने की आजादी में रुकावट पड़ती है। मगर फैक्ट चेक करने यानी तथ्यों की जांच करने से बोलने की आजादी में खलल कहां पड़ता है। असल में एनरॉन खुद ही फैक्ट चेकिंग में आगे रहती थी और धरती को चपटी बताने वाले जो चाहें लिख सकते हैं।

लेकिन जहां आग न लगी हो वहां आग-आग चिल्लाने से भगदड़ मच सकती है। किसी हत्यारे की पृष्ठभूमि के बारे में भ्रामक जानकारी डालने से दंगे भड़क सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे चोट्टों के पेट के कीड़े मारने वाली दवा को कोविड-19 की दवा बताते रहना। इससे तो महामारी और भी फैलती जाएगी।

केवल भ्रामक जानकारी देने या नफरत फैलाने वाले विचार रखने पर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म नहीं की जाना चाहिए। इस पर तभी अंकुश लगाया जाना चाहिए जब इससे हानि पहुंचने की आशंका हो। दुर्भाग्य है कि फैक्ट चेकिंग की सुविधा भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर जाने से रोक नहीं सकती। मगर यह छन्नी का काम जरूर करती है, जिससे नुकसान कम करने में मदद मिलती है। अब फैक्ट चेकिंग सुविधा हटाई जा रही है तो इसलिए साउथपोर्ट जैसे कई और दंगे भड़क सकते हैं।

आपका पक्ष

ट्रंप की नीतियों से सीख

डॉनल्ड ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यापार संतुलन में बदलाव के संकेत देते हैं। अमेरिका में विनिर्माण बढ़ाने और आयात पर कर लगाने की उनकी घोषणा, भारत जैसे देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि यह संकट अवसर बन सकता है अगर भारत अपनी नीतियों में सुधार करे। विदेशी निवेश में संभावित कमी से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा, जिससे आयात महंगा हो सकता है। लेकिन यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। सरकार को चाहिए कि विदेशी माल पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करे। इसके अलावा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सुधार जरूरी है। ट्रंप की नीतियां यह सिखाती है कि चुनौतियां केवल बाधा नहीं होती वे नई दिशा में सोचने और कार्य करने का अवसर भी देती है। सही नीतिगत फैसले लिए जाएं तो भारत इस संकट को अपनी आर्थिक सुदृढ़ता में बदल सकता है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने से पहले डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार रात एक समारोह को संबोधित किया

रोजगार सृजन हो प्राथमिकता

आम बजट का मुख्य ध्येय मध्यम वर्ग और किसानों को राहत देने के साथ ही रोजगार सृजन करने वाला होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देते हुए कर प्रणाली को सरल तथा आयकर छूट एवं मानक कटौती की सीमा बढ़ाई जाना चाहिए। लघु व्यवसाय, स्टार्टअप के प्रोत्साहन देने की अपेक्षा है।

वर्षा अग्रवाल, भोपाल

आयकर में मिले राहत

आर्थिक मंदी के इस दौर में ऐसे चुनौतीपूर्ण बजट की अपेक्षा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा रोजगार सृजन, कृषकों की स्थिति में सुधार के साथ ही मध्य वर्ग को आयकर में राहत अपेक्षित है। मध्यम और लघु व्यापारियों को कर में राहत देना भी समय की मांग है।

रमेशचंद्र कर्नावट, उज्जैन

विकसित भारत बनाने वाला हो बजट

उम्मीद है कि मोदी सरकार का आम बजट देश को विकसित भारत की योजनाओं को प्रकट करेगा और आम जनता के सपनों को पूरा करने की दिशा में आएगा। बजट का ज्यादा हिस्सा देश की सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेल विकास पर खर्च होगा। साथ ही बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर होगा। सरकार को बेरोजगारी कम करने और शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशकों को ज्यादा छूट देने का काम करना चाहिए। विकसित भारत बनने का रास्ता उद्योगों के मजबूत होने से ही मिलेगा।

डॉ उमेश मित्तल, सहारनपुर

बजट में मुफ्त की घोषणाओं से बचा जाए

महंगाई नियंत्रण व रुपये की मजबूती के लिए मुफ्त की घोषणाओं से बचना चाहिए। पेंशन के बढ़ते बोझ से बचने के लिए अधिकतम सीमा तय करना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन मात्र एक हजार न्यूनतम है। इसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। जिन म्युचुअल फंड एजेंट का कमीशन तीन लाख रुपये वार्षिक से कम हो उन्हें जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए।

विनोद काबरा, बेदनगर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

इजरायल ने हमास के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत सोमवार तड़के 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इससे कुछ घंटों पहले ही हमास ने तीन इजरायली बंधकों को रिहा किया था जो अपने देश पहुंच गए हैं।

ट्रंप का आगमन

दूसरा कार्यकाल

डोनाल्ड ट्रंप से अपने दूसरे कार्यकाल में घरेलू नीतियों में परिवर्तन के साथ दुनिया में अमेरिका की भूमिका पुन: परिभाषित करने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया जो अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि चीनी उप-राष्ट्रपति हैन झेंग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया जो आने वाले वर्षों में अमेरिका-चीन संबंधों का महत्व दिखाता है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत अनेक निर्णायक कार्रवाइयों से होगी। उन्होंने पहले ही दिन कार्यालय में लगभग 100 कार्यकारी आदेशों की योजना बनाई थी जिनमें आप्रवासी, व्यापार और ऊर्जा को केन्द्रीय स्थान मिला है। इन आदेशों का उद्देश्य अवैध आप्रवासियों का निष्कासन, जन्म से नागरिकता का अधिकार समाप्त करना तथा 'मुस्लिमों पर प्रतिबंध' पुन: लागू करना शामिल है। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने, टैक्स घटाने तथा विनियमन कम करने की योजना बनाई थी। ट्रंप ने 'हरित ऊर्जा पहलों' को घटा कर फ़ासिल ईंधनों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। उनकी सांस्कृतिक नीतियों में ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर करना तथा नाबालिगों के लिए हारमोन चिकित्सा को सीमित करना शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चीन के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण आक्रामक है। उन्होंने आयातों पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने की बात कही थी।

अमेरिकी डालर का प्रयोग रोकने की स्थिति में इनको चीन व रूस जैसे ब्रिक्स देशों के लिए बढ़ा कर शत प्रतिशत करने का इरादा था। इसके साथ ही ट्रंप ने फेंटानिल जैसे नशे के व्यापार तथा अमेरिका में चीनी टिकटाक जैसी कंपनियों पर रोक लगाने के संकेत पहले ही दिए थे। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक हालिया फोन वार्ता में व्यापार, फेंटानिल व टिकटाक जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इससे संकेत मिलता है कि चीन और अमेरिका के बीच संभवत: जटिल व विवादास्पद संबंधों का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय कंपनियों तथा टेक्‍ पेशेवर भारतीयों के लिए अमेरिका में एच-1बी वीसा का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में अवसरों और चुनौतियों की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों से लगातार सहयोग बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध बहुत अच्छे रहे हैं जिसमें ट्रंप व मोदी के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों ने उल्लेखनीय योगदान किया था। लेकिन ट्रंप की 'अमेरिका प्रथम' नीतियों से व्यापार के मुद्दों पर खासकर सूचना प्रौद्योगिकी व फर्मास्यूटिकल्स के मामलों में तनाव पैदा हो सकता है जहां भारत के काफी हित निहित हैं। इन संभावित बाधाओं के बावजूद हिंद-प्रशांत में भारत का रणनीतिक महत्व तथा उसकी भूमिका बढ़ सकती है। इसके साथ ही वैश्विक सप्लाई श्रृंखला के चीन से आगे बढ़ कर विविधीकरण से भारत को लाभ हो सकता है और इससे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के अपने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश के समय सारी दुनिया उनके प्रशासन की नीतियों पर नजरें जमाए है। देखना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत और चीन पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों का कैसा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा आगे आने वाले महीनों में लिए गए निर्णयों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा तथा राजनयिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।

एलपीजी सब्सिडी: तार्किकीकरण जरूरी

एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने से सरकारी कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार ने वित्तीय बोझ सहन करने के लिए 35,000 करोड़ सब्सिडी दी है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं।)

यदि केवल एलपीजी सब्सिडी को गरीब परिवारों तक सीमित रखने तथा इसे पारदर्शी बनाने के पहले के निर्णय पर अमल किया गया होता तो सरकार को यह बोझ न उठाना पड़ता। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में ऐसा सोचना लगभग असंभव है क्योंकि सभी निर्णय आर्थिक नीति के आधार पर सटीक होने के बजाय लोकरंजकता से प्रभावित होते हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी कंपनियों इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड-आईओसी, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड-बीपीसीएल तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड-एचपीसीएल को सस्ते दामों पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई करने पर क्रमश: 19550 करोड़, 10400 करोड़ तथा 10570 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार कुल 40,500 करोड़ रुपये नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। 1 फरवरी, 2025 को पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में 10,000 करोड़ तथा 2025-26 के बजट अनुमानों में बाकी 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेंगी। घाटे का कारण यह है कि इन निगमों ने एलपीजी प्रति 14.2 किलो 803 रुपये प्रति सिलिंडर बेची, जबकि खुदरा बिक्री बिंदुओं पर इसका खर्च अधिक था। कीमत का हिसाब रिफाइनरी-गेट कीमत या आरजीपी पर किया जाता है और इसमें माल भाड़ा, मार्केटिंग खर्च, मार्केटिंग मुनाफा, डीलरों का कमीशन तथा टैक्स व ड्यूटी जोड़ी जाती हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में यह लागत 1043 रुपये प्रति सिलिंडर आती है और इस प्रकार प्रति सिलिंडर 240 रुपये घाटा होता है जो कुल 169 करोड़ सिलिंडरों की बिक्री पर 40,500 करोड़ रुपये हो जाता है। मोदी सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी वित्त वर्ष 2021-22 में देनी बंद कर दी थी। फिर बजट से इसके लिए भारी भुगतान क्यों करना पड़ता है? एलपीजी एक पर्यावरण तथा मानव -स्वास्थ्य हितैषी ईंधन है, इसलिए सरकार इससे करोड़ों परिवारों की आवश्यकता पूरी करती है। सरकार केवल गरीब परिवारों को एलपीजी पर सब्सिडी देती है। सरकार को लाभार्थियों के आय पर नजर रखते हुए बेहतर स्थिति में पहुंचे ऐसे लोगों की सब्सिडी हटानी पड़ती है जो इसके भुगतान में सक्षम होते हैं और उनसे लागत का दाम वसूल किया जाता है। लेकिन इन महत्वपूर्ण सिद्धानों की अनदेखी कर एलपीजी कनेक्शन धारक सब लोगों को सब्सिडी दी गई। यह अमीरों समेत सबको मिली। ऐसे में इसे प्राप्त करने वाले गरीब लोग हाशिए पर रह गए। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सब्सिडी का केवल 0.07 प्रतिशत पहुंचता है और इस प्रकार इसका केवल पांचवां भाग ही गरीब परिवारों को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में भी सबसे गरीबों को केवल 8.2 प्रतिशत लाभ मिलता है।

इस प्रकार काफी सब्सिडी फर्जी लाभार्थियों तक पहुंच जाती है जिसका कारण एलपीजी सिलिंडरों का होटलों, रेस्टोरेंटों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग है। औचित्य की अनदेखी कर केवल लोकरंजकता के कारण ही एलपीजी सब्सिडी सबको दी जाती है। वे केन्द्र सरकार की बैलेंसशीट पर बोझ डाले बिना इसे पाने का रास्ता खोज लेते हैं। शुरुआत में एलपीजी पर सब्सिडी की भरपाई अन्य उत्पादों, जैसे फ्यूल आयल, नेफ्था, एटीएफ आदि की बिक्री मूल्य बढ़ा कर की जाती थी जिसका बजट पर कोई बोझ नहीं पड़ता था। 2002-03 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर इन उत्पादों पर सीधे बजट से सब्सिडी देने का निर्णय किया। इसके पीछे इरादा इसे अंतत: समाप्त करना था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। 2004 में सत्ता में आई संप्रग सरकार ने सस्ती बिक्री जारी रखते हुए आईओसीएल, बीपीसीएल व एचपीसीएल को 'तेल बांड' जारी करने की नीति अपनाई जो इन उत्पादों के लागत से कम पर बिक्री की भरपाई के लिए थे। इसमें सरकारी तेल कंपनियों व गैस कंपनियों आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन-ओएनजीसी तथा आयल इंडिया लिमिटेड-ओआईएल द्वारा बेचे जाने वाला घरेलू कच्चा तेल भी शामिल था। जून 2010 में पहले पेट्रोल तथा नवंबर, 2014 में डीजल को नियंत्रण कसे बाहर कर दिया गया। जहां तक एलपीजी का सवाल है, केलकर कमेटी ने 2012-13 में 25 प्रतिशत तथा इसके दो साल बाद 75 प्रतिशत सब्सिडी समाप्त करने की संस्तुति की थी। मई, 2014 में सत्ता संभालने पर मोदी सरकार ने सुनियोजित ढंग से काम करना शुरू किया। 1 जनवरी, 2015 को उसने सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-डीबीटी योजना शुरू की। डीबीटी के अंतर्गत तेल पीएसयू ने लाभार्थियों को पूरी लागत पर लाभार्थियों को सिलिंडर दिए और इसके बाद सब्सिडी को लाभार्थियों के खातों में जमा करने की व्यवस्था की गई। इसके बदले वे केन्द्र से सब्सिडी भरपाई की मांग कर सकती थीं। इस व्यवस्था ने फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना शुरू किया तथा पुरानी व्यवस्था में अंतर्निहित दुरुपयोग पर लगाम लगी जहां सब्सिडी को कीमत के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन सरकार लाभार्थी परिवारों की संख्या घटाने का साहस नहीं कर सकी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमीर परिवारों से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की प्रार्थना की जिसका थोड़ा असर भी हुआ। सब्सिडी के दृष्टिकोण से वित्त वर्ष 2020-21 बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी कमी आई जिससे एलपीजी सिलिंडर की कीमत घट कर 600 रुपये रह गई। इस प्रकार यह बिना किसी सब्सिडी के सभी परिवारों को 600 रुपये में दिया जा सका। इस वर्ष बजट में निर्धारित 36,000 करोड़ रुपये मुख्यत: तेल पीएसयू को पुराने खामियाजे की भरपाई के लिए किए गए तथा प्रधानमंत्री ऊज्जवला योजना-पीएमयूवाई के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। वित्त वर्ष 2021-22 में जब कोविड घटने से अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं और मांग भी तेज हुई तब एलपीजी सिलिंडर की कीमत बढ़ कर 900 रुपये प्रति सिलिंडर पहुंच गई।

इसके बाद सरकार ने केवल पीएमयूवाई लाभार्थियों को सब्सिडी देने की घोषणा की। उनकी संख्या कुल 33 करोड़ परिवारों में 9.6 करोड़ थी। उसने इस पर उस साल 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए। वित्त वर्षज्ज 2022-23 में उसने 9,170 करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन सरकार ने जून, 2020 से जून, 2022 के बीच तीन ईंधन रिटेलरों-आईओसीएल, बीपीसीएल, व एचपीसीएल की घोषणा की जो एलपीजी लागत से कम कीमत पर बेचते थे और उनको इसके लिए 22,000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया, हालांकि कुल खर्च 28,250 करोड़ था। यह भी एक प्रकार से सबको दी जाने वाली सब्सिडी थी। 2023-24 के बजट में एलपीजी सब्सिडी के लिए 2,257 करोड़ रुपये रखे गए। इसका उद्देश्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को सब्सिडी देना था। जिनको 200 रुपये प्रति सिलिंडर के हिसाब से साल में 12 सिलिंडर दिए जाते थे। लेकिन सभी 33 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रति सिलिंडर 200 रुपये कीमतें कम करने की घोषणा की जो 30 अगस्त, 2023 से लागू हुई। इससे पीएसयू पर हर साल 26,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। 9 मार्च, 2024 को ईंधन खुदरा विक्रेताओं को प्रति सिलिंडर 100 रुपये और घटाने का निर्देश दिया गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में इस मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि लागत बढ़ी है। इस कारण 2023-24 तथा 2024-25 में 40,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जिसकी भरपाई के लिए केन्द्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके साथ ही पहले आईओसीएल, बीपीसीएल व एचपीसीएल को घाटे की भरपाई के लिए भी 22,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यदि केवल एलपीजी सब्सिडी को गरीब परिवारों तक सीमित रखने तथा इसे पारदर्शी बनाने के पहले के निर्णय पर अमल किया गया होता तो सरकार को यह बोझ न उठाना पड़ता। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में ऐसा सोचना लगभग असंभव है क्योंकि सभी निर्णय आर्थिक नीति के आधार पर सटीक होने के बजाय लोकरंजकता से प्रभावित होते हैं।

हृदय मन और ईश्वर से जुड़ाव

रवि बलूरी
(लेखक आर्ट ऑफ लिविंग के संकाय सदस्य हैं।)

आज हम सिर्फ दोस्ती के बंधन से ही नहीं बल्कि तकनीक के धागों से भी जुड़े हुए हैं। तीन दशक पहले, हम शायद सिर्फ़ कुछ अलग-अलग दोस्तों और परिचितों का समूह थे। हम एक ऐसे युवा और छोटी कद-काठी की महिलाएँ थीं जो किशोरावस्था से ही एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ती थीं। तीन दशक पहले हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण से पहले के दौर में वाम, दक्षिण और मध्यमार्गी राजनीतिक विचारधाराओं की विविधता को मानते और संजोते थे। यह एक पीढ़ी पहले की बात है। इस बीच, सोवियत अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बिखर गई, बर्लिन की दीवार ढह गई और विभिन्न देशों ने तेज़ी से उपभोक्तावाद और पूंजीवाद को अपना लिया। एक जादुई ज़ुकरबर्ग ने जान कौम से व्हाट्सएप नामक एक उपकरण खरीदा। सभी तकनीक और गैजेट ने निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान की है और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक पल में, हम सभी व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ गए। व्हाट्सएप पर कुछ महीनों तक लगातार चैटिंग के बाद पुनर्मिलन की घोषणा हुई। इसके बाद जोरदार तैयारियां की गईं और जयपुर के आलीशान राजपुताना शेरटन में घर वापसी हुई। यह मिलन और जुड़ाव वाकई अद्भुत था। तीन दिन और चार रातों के लिए हमें अपने पुराने बोझ को उतारकर एक नई ज़िंदगी जीनी थी। बीते दिनों के दोस्त बच्चों के एक समूह की तरह अपनी जड़ों को फिर से खोज रहे थे। यह पूरी तरह से एक शारीरिक तड़प है। मानव मन की ज्यामिति और वास्तुकला बेखबर, बेखबर और उस उच्च, ऊंचे और महान स्थिति से अनजान है जिसकी वह क्षमता रखता है। यह ईश्वर के लिए तड़प और लालसा है। वही तड़प जो राधा अर्जुन या सुदामा में भगवान कृष्ण के लिए थी।

यह सभी धर्मों, आस्थाओं और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए सच है। जैसे यूसुफ, दाऊद, सुलेमान और इब्राहिम ने अल्लाह को पुकारा। जैसा कि प्रेरितों ने और हाल ही में संत टेरेसा ने ईसा मसीह के लिए या आनंद ने बुद्ध के लिए महसूस किया था। यह बिना किसी लगाव और उलझन के दिव्य प्रेम है। यह लालसा की भावना नहीं है, बल्कि

पाँच ई की भावना है। ये पाँच ई क्या हैं? भक्त, साधक और श्रद्धालु उल्लास, परमानंद, उल्लास, उल्लास और उमंग से युक्त हैं। यह ईश्वर के लिए प्रामाणिक और सच्ची तड़प है। यह एक ध्यान की अवस्था है जिसमें साधक या शिष्य गुरु की महिमा में डूब जाता है और तीन सी के सिद्धांत के साथ उनका नाम लेता है- विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास। हाँ, प्रबुद्ध बुद्ध कहते हैं कि जीवन में

ईश्वर के लिए तड़पता हुआ दिल और दिमाग सत्य है। यह सभी सीमाओं को पार कर जाता है। भावनाएँ और संवेदनाएँ रचनात्मक और प्रभावकारी विचारों से मानव मन को घेर लेती हैं, जहाँ वह किसी भी दुस्साहस को पार करने और उससे पार पाने के लिए निडर हो जाता है।

कुछ भी स्थायी नहीं है, और नश्वरता ही एकमात्र स्थिर कारक है। हालाँकि, ईश्वर के लिए तड़पता हुआ दिल और दिमाग सत्य है। यह सभी सीमाओं को पार कर जाता है। भावनाएँ और संवेदनाएँ रचनात्मक और प्रभावकारी विचारों से मानव मन को घेर लेती हैं, जहाँ वह किसी भी दुस्साहस को पार करने और उससे पार पाने के लिए निडर हो जाता है। आगे विस्तार से बताते हुए, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एक टीज़र पेश करते हैं, क्या हम ईश्वर को गुणवत्तापूर्ण समय देते हैं? वे आगे कहते हैं, कि हम ऐसा केवल पार्टी करने, कुछ लुभावनी फ़िल्में देखने और मेहमानों का मनोरंजन करने के बाद ही करते हैं। हमारे समय का शेष भाग या संतुलन मन द्वारा ईश्वर की आराधना के लिए अलग रखा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड हम पर केवल आशीर्वाद और उदारता की मात्रा बरसाता है, जो हमारे तप या मन के प्रयास पर निर्भर करता है। हालाँकि, योग, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया की अनूठी लयबद्ध श्वास तकनीक जैसी तकनीकों के व्यवस्थित और सटीक अभ्यास के माध्यम से, मन वर्तमान क्षण में रहकर ईश्वर के साथ निरंतर संवाद की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो, तीस साल बाद मिले समूह का क्या हुआ? वे स्थायी और निरंतर संपर्क में हैं। शायद भीतर और बाहर से बंधन को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक चमक की एक झलक की आवश्यकता है।

आप की बात

ट्रंप का राष्ट्रपति बनना

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। ट्रंप की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ की विशेषता है जो भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप की आव्रजन नीतियों में बदलाव से भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अमेरिका में काम करना और पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों में मजबूती आ सकती है। ट्रंप ने अपने अभियान में भारत के साथ सामरिक संबंधों को मजबूत करने का वादा किया था। इसके अलावा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर खुल सकते हैं। ट्रंप की आर्थिक नीतियों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का जोर है जो भारतीय कंपनियों के लिए लाभप्रद हो सकता है। यदि चीन पर ट्रंप सो प्रतिशत टैरिफ लगाता है तो भारतीय उद्योगों को अपना माल निर्यात करने में सुविधा होगी। इस प्रकार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में कई परिवर्तन हो सकते हैं। इन परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

-विभूति बुपक्या, खाचरोद

न्याय व्यवस्था

अति अति गंभीर अपराध के लिए भी कई बार कम गंभीर सज़ा दी जाती है क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था मुख्यत: गवाही पर निर्भर होती है और कई बार गवाही गलत भी हो सकती है। यदि गवाह निष्पक्ष न हो, गवाह ने जो देखा या सुना उसमें भ्रम हो, गवाह को अतिविश्वास हो कि आरोपी अपराधी हो ही नहीं सकता, गवाह की घटना के विश्लेषण की क्षमता न हो, गवाह को पीड़ित से विद्वेष हो, गवाह भाषा या शब्द ज्ञान की कमी के कारण घटना का विवरण या व्याख्या देने में सक्षम न हो आदि कई कारण हो सकते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन को वैज्ञानिक विधियों जैसे सीसीटीवी, ब्लैक बॉक्स जैसी व्यवस्थाओं का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग, गवाह के मस्तिष्क का विश्लेषण और झूठ पकड़ने वाली प्रणालियों का विकास, घटनाओं के अध्ययन के लिए पशु पक्षियों की क्षमताओं का उपयोग और नई वैज्ञानिक विधियों के आविष्कार और विकास करना चाहिए। न्याय का एक सिद्धांत यह भी है कि सौ दोषी भले छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस सिद्धांत के कारण बहुत से दोषी न्यायालय से छूट जाते हैं और पुन: समाज में अपराध करते हैं। इसलिए हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी को न्याय मिल सके। साथ ही समय से न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

-ललित दुबे, कस्तूरबा नगर,, रतलाम

बेहतर प्रबंधन जरूरी

आकस्मिक घटनाएं और आपदाएं किसी भी समय आ सकती हैं लेकिन इनसे निपटने के लिए तत्परता और बेहतर प्रबंधन अनिवार्य हैं। हाल ही में प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आगजनी की घटना ने यह सिखाया कि यदि प्रशासन सतर्क और तत्पर हो तो बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। आगजनी की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए और फायर ब्रिगेड ने कुछ ही मिनटों में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। यदि प्रशासन सतर्क न होता तो यह आग विकराल रूप ले सकती थी और जान-माल की भारी क्षति होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों का निरीक्षण करना उनके नेतृत्व और आपदा प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घटना की जानकारी लेना और अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देना यह साबित करता है कि आपदा प्रबंधन में उच्च स्तर पर समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा के मानकों को और मजबूत करना चाहिए। प्रशासन की तत्परता और समर्पण ने यह साबित किया कि बेहतर प्रबंधन न केवल घटनाओं पर नियंत्रण पाता है बल्कि लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का माध्यम भी बनता है।

-प्रो. आरके जैन अरिजीत, बड़वानी

पशुपालन को मिले बढ़ावा

सरकार द्वारा सर्वजन सुखाय के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों को राशन से लेकर घर तक उपलब्ध कराया गया। अब लोगों को सोचना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि वे गायों को पाले और उनको अक्षा न छोड़ें। सरकार निराश्रित गायों के लिए गो शालाओं की व्यवस्था कर रही है। उनके लिए आहार उपलब्ध कराने के लिए धन दे रही है। लेकिन इसे देखने वाला प्रबल निगरानी तंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था और उन्हें हरा चारा गोशालाओं को किसानों से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। किसानों से हरा चारा खरीदने पर उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री गायों के कल्याण के लिए पशुपालन अधिकारियों से हर जिले में हरे चारे की खपत का आकलन करने और हरे चारे के लिये वेयर हाउस बनाने की बात कही तथा इसकी निगरानी जिलाधिकारी को करने को कहा है। मुख्यमंत्री को गाँवों में चारागाहों और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर लोगों को पशुपालन के लिये सुविधा देना चाहिए। आज लोगों को पशुओं को चराने के लिये चारागाह और पानी पिलाने के लिए तालाब नहीं है।

- कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 21 जनवरी 2025

बयानों पर FIR

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सोमवार को स्टे लगा दिया। दिलचस्प है कि इससे पहले शनिवार को ही उनके खिलाफ असम पुलिस ने गुवाहाटी में एक FIR दर्ज की। दरअसल, देश में राजनीतिक बयानों पर कोर्ट में केस करने या FIR दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति कई सवाल खड़े करती है।

राजनीतिक बयान | ऊपर जिन दो मामलों का जिक्र किया गया है, उनमें राहुल के बयान राजनीतिक प्रकृति के हैं। मानहानि के केस में राहुल गांधी के उन बयानों पर आपत्ति जताई गई है, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर BJP सदस्यों को झूठा और सत्ता के नशे में डूबा बताया है। गुवाहाटी में दर्ज FIR का वास्ता उनके उस बयान से है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारत राज्य से संघर्ष की बात कही थी।

AI Image

राहुल गांधी को राहत

हावी होता सरकारी तंत्र | बात राहुल गांधी की हो या किसी अन्य नेता की, उनके बयानों से सहमत होना जरूरी नहीं है। यह दलील भी नहीं दी जा सकती कि बड़े राजनीतिक दलों के नेता देश के कानून से ऊपर हैं। अगर वे किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन जब किसी लोकतंत्र में राजनीतिक बयानों को कानून व्यवस्था के सरकारी तंत्र के जरिए नियंत्रित करने का प्रयास होने लगे तो उसे अच्छा नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकारें भी पीछे नहीं | दिक्कत यह भी है कि ऐसा अगर किसी एक पार्टी की सरकार में होने लग जाए तो दूसरे दल भी जहां उनकी सरकारें हैं, वहां पीछे नहीं रहते। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जब सत्तारूढ़ दल या नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर FIR दर्ज की गई।

बड़े नेताओं से उम्मीद | हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे तमाम मामलों में सरकार और पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति शामिल होती है। लेकिन ये बड़े नेता चाहें तो इस प्रवृत्ति पर रोक जरूर लगा सकते हैं। याद रखना चाहिए जिन पड़ोसी देशों में लोकतंत्र का मजाक बनता हुआ हम देखते हैं, उन सबमें विरोधी राजनीति को कानून की बलि चढ़ाकर ही सत्तातंत्र वहां तक पहुंच पाता है।

धूप-छांव

क्या करें, क्यों करें

प्रणव प्रियदर्शी

कहते हैं, एक बार दो चीलें आसमान में साथ उड़ रही थीं। तभी एक हवाई जहाज उधर से गुजरा। जब तक ये कुछ देख-सुन पातीं, हाय-हेलो कर पातीं, हवाई जहाज दूर जा चुका था। एक चील दूसरे से बोली, 'बहन, वह चील कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं थी? हमारी तरफ देखा तक नहीं, सीधे निकल गई।' दूसरी ने थोड़ी-बहुत दुनिया देख रखी थी। बोली, 'अगर तुम्हारी भी पूंछ में आग लगी होती तो तुम भी ऐसे ही भागती।'

आजकल हम सबकी पूंछ में आग लगी हुई है। हम सीधे-सरपट भाग रहे हैं। जल्दी इतनी है कि यह सोचने की भी फुरसत नहीं कि यह जल्दी आखिर क्यों है? चूंकि सबको है, इसलिए यह जल्दी अकारण नहीं हो सकती। इक्का-दुक्का लोग होते जल्दी में तो उनका पागलपन या उनकी कोई खास समस्या मानकर उसे अनदेखा किया जा सकता था। चूंकि आग सबकी पूंछ में लगी है तो पूछना बनता है कि यह आग है कैसी। किसने लगाई? क्या कहीं कोई बंदा है जो एक-एक कर सबकी पूंछ में आग लगाकर भाग जाता है? लेकिन सकारण हो या अकारण, आग होगी तो उसकी तपन भी होगी, उससे बेचैनी भी होगी। लिहाजा, सबके चेहरों पर चौबीसों घंटे बेचैनी के निशान भी दिखते रहते हैं। जो कुछेक लोग ऐसे मिलते हैं, जिनके चेहरे पर कोई बेचैनी के भाव नहीं हैं, जिन्हें किसी बात की जल्दी नहीं है, उनके जीवन पर गौर करें तो वे सबसे दयनीय लगते हैं। इनमें से ज्यादातर को खुद अपना जीवन ही जैसे बेमकसद लगने लगा है। क्या करें और क्यों करें- उनके दोनों ही प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बेमानी जल्दबाजी और बेजान शांति- ये दो विकल्प ही हमारी नियति बन चुके हैं?

सामूहिक स्तर पर, मनुष्य समाज के स्तर पर देखें तो उसकी निरंतर सक्रियता या उससे उपजी जल्दबाजी बेमानी तो कतई नहीं लगती। इसने उसे असाधारण, अभूतपूर्व उपलब्धियों से नवाजा है। लेकिन सारी उपलब्धियां मिलकर भी इस ग्रह को पहले से ज्यादा बदसूरत, ज्यादा असुरक्षित बना रही हैं। क्या यह ठोस वजह नहीं कि इस निरंतर सक्रियता की सार्थकता को गंभीरता से सवालों के दायरे में लाया जाए?

बोल वचन

कटनी काटकर

राहुल पाण्डेय

नाटे हमारी फुटबॉल टीम के मैराडोना भी थे और पेले भी। खेल के दौरान ऐसी-ऐसी कटनी मारते थे कि सामने वाला दंग रह जाए। फुटबॉल दाहिने मारें और खुद बाईं ओर से खिलाड़ी को काटकर झटपट फुटबॉल अपने कब्जे में ले लें। कटनी मारना एक कला है। अवधी में कटनी मतलब घूमकर चलना या भागना, तो बुंदेली में तिरछी दौड़। मध्य प्रदेश में भी एक कटनी है, जिसे संगमरमर का शहर कहते हैं। कटनी नदी भी है। कटनी फसल काटने वाला औजार है, तो फसल को काटना भी है। कटनी से आम से लेकर साग तक काटा जाता है। कपड़े की काट-छांट भी कटनी है। ब्रज में कटनी काटने के बाद मिलने वाली मजदूरी है, तो फसल काटने का समय भी है। जोतने से पहले कुदाल से खेतों की घास साफ करने को भी कटनी कहा जाता है। नदी भी कटनी करती है, यानी किनारों को काटती चलती है। बिहारी कहते हैं, 'करत जातु जेती कटनि बढ़ि रस-सरिता-सोतु। अलबाल उर प्रेम-तरु तिती तिती दुढ़ होतु।' मतलब, रस-रूपी नदी का स्रोत बढ़कर जितना ही कटाव करता जाता है, हृदय-रूपी थाने का प्रेम-रूपी वृक्ष उतना ही मजबूत होता जाता है। कटनी के इतने सारे अर्थों को किसी एक शब्द में समेटने में इंग्लिश ने भी लगता है कि कटनी ही काट ली है। उसके पास कटनी के हर अर्थ के लिए अलग शब्द हैं।

Subrata Dhar

संघ प्रमुख के बयान पर नहीं, मौजूदा विवाद उस बात को लेकर है जो भागवत ने कही ही नहीं

क्या अपने 'झूठ' में ख़ुद फंस गए राहुल

अवधेश कुमार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा इंदौर के एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए वक्तव्य से देश में बवंडर मचा हुआ है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि संघ 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता दिवस मानता ही नहीं और भागवत ने 22 जनवरी, 2024 यानी पौष शुक्ल द्वादशी से स्वतंत्रता दिवस मानने और मनाने की अपील की है।

भारतीय राज्य से संघर्ष | उसके बाद राहुल गांधी का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है कि भागवत ने जो कहा, वह संघ का विचार है और हम उसी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपने केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहां तक कह दिया कि यह मत मानिए कि हमारा संघर्ष केवल संघ और BJP जैसे किसी राजनीतिक संगठनों से है। हमें पूरे इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य से संघर्ष करना है।

सपने साकार होंगे | संघ प्रमुख के इंदौर के भाषण के विडियो उपलब्ध हैं। इसमें वह कह रहे हैं, 'भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि, जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वह संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं, उसके अनुसार चला नहीं और इसलिए, 'हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें।'

गांधी की आपत्ति | महात्मा गांधी ने 15 अगस्त, 1947 को कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि क्या ऐसे ही स्वराज के लिए हमने संघर्ष किया था? उन्होंने स्पष्ट लिखा कि हमें अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई किंतु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए पहले से ज्यादा लंबे संघर्ष और परिश्रम की आवश्यकता है। क्या इस आधार पर आप गांधी जी को स्वतंत्रता दिवस विरोधी घोषित कर देंगे?

विरोधियों का झूठ | भागवत की अगली पंक्ति भी देखनी चाहिए, 'स्वतंत्रता में जो स्व का अधिष्ठान होता है, वह लिखित रूप में हमने संविधान से पाया है, लेकिन अपने मन को उसकी पक्की नींव पर आरूढ़ नहीं किया है। हमारा स्व क्या है? राम, कृष्ण, शिव, ये क्या केवल देवी-देवता हैं, या केवल उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं।' उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पौष शुक्ल द्वादशी को स्वतंत्रता दिवस मनाना है।

मुक्ति का सतत संघर्ष | थोड़ा दुष्प्रचारों से अलग होकर सोचिए कि आखिर आक्रमणकारियों ने हमारे धर्मस्थलों पर हमले कर उनको ध्वस्त क्यों किया? इसीलिए कि हमारा स्व मर जाए। उन स्थलों, प्रतिस्थापित प्रतिमाओं या निराकार स्वरूपों को लेकर हमारे अंदर का आस्था विश्वास नष्ट हो। आक्रमण, ध्वंस, जबरन निर्माण और दासत्व के समानांतर प्रतिकार व मुक्ति के संघर्ष सतत चलते रहे। गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, लाचित बरफुकन आदि हमारे लिए स्वतंत्रता के महान सेनानी थे या नहीं?

RSS प्रमुख ने आखिर कहा क्या

- 1947 में सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली
- संविधान में भारत के स्व से निकली दृष्टि
- आजादी के बाद इस दृष्टि पर अमल नहीं

संस्कृति का प्रतीक | इस संदर्भ में अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति का आंदोलन किसी के विरोध के लिए नहीं, स्व जागृत करने और पाने के लिए था। भागवत ने कहा कि यह दिन अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया है। जिनके लिए अयोध्या आंदोलन ही गलत हो वे इस भाव को नहीं समझ सकते।

झूठ फैलाना गलत | फिर भी यह स्वीकार किया जा सकता है कि किसी का भागवत या संघ की सोच से मतभेद होगा। किंतु जो उन्होंने कहा, बहस उस पर होगी या जो कहा नहीं, उस पर? क्या इस तरह का झूठ फैलाना संविधान की प्रतिष्ठा है?

नक्सलियों की बोली | सच यह है कि भागवत का भाषण नहीं होता तब भी किसी बहाने राहुल गांधी को यह सब बोलना ही था। वह परंपरागत माओवादी, नक्सलवादी या आरंभिक कम्युनिस्टों की तरह की भाषा लगातार बोल रहे हैं। वे लोगों को भड़काने के लिए यही बोलते थे कि धार्मिक कट्टरपंथियों, फासिस्ट शक्तियों का विस्तार हो रहा है, पूंजीपति-उद्योगपति शोषण के आधार पर सत्ता का लाभ लेते हुए धन इकट्ठा कर रहे हैं और इसलिए राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं।

कांग्रेसी भी विचार करें | वास्तव में संघ प्रमुख ने एक संतुलित विचार दिया, लेकिन राहुल गांधी की बात हिंसा और उत्तेजना पैदा करने वाली है। कांग्रेस नेताओं को भी विचार करना चाहिए कि क्या इस सोच से उनका जनसमर्थन बढ़ेगा? क्या यह उन मूल्यों पर आघात नहीं होगा जिनके लिए स्वतंत्रता संघर्ष हुआ?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

वांदा नईं भीड़! आज़ादी का कोई बी डेट चलेंगा

दीपक पाचपोर

वो दिन सुबू-सुबू अपुन का फ्रेंड बाबूराव मस्त प्रवचन दिएला- 'कदी-कदी लगताए भिड़, ऊपर वाला अक्खा दुनिया कों मुलुक जबी बी बनाएला मौत घाई-गर्दी में बनाएला। खाली अपुनईच का कंट्री फुलटू खाली पीली बईठ के बनाएला। बाकी का कंट्री बनाने का बखत जो बी गलती से मिस्टेक हुएला, उसका दुरुस्ती इदरईच बईठ के किएला। सोचा होएंगा कि इसकूं टोटल झक्कास बनाना मांगताए। तुम पूछेंगा कि वो कईसा? बोले तो कोई-कोई कंट्री का भीतर पहाड़ नईं बनाएला तबी इदर सबका बाप हिमालय दिएलाए। किदरकूं दरया नईं होएंगा पन इदर इत्ता नदी दिएलाए कि तुम गिनने कूं नईं सकताए। कोई-कोई मुलुक का भीतर तुमकूं रेगिस्तान का तुकड़ा बी नईं मिलेंगा। इदर तुमकूं एक नईं दो-दो डेजर्ट गिफ्ट किएला...'

अपुन बोला- 'बस क्या प्रोफेसर बाबूराव! ज्यॉग्रफी का क्लास लेताए क्या? एटलस दिखाने का जरूरत नईं। इत्तईच बताने का कि तुमकूं शॉर्ट में क्या केना मांगताए? रील बनाने का, फुलटू वीडियो देखने का अपुन का पास टाइम नईं होताए।'

कोई बी उसका बोल बच्चन पे इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगा तबी बाबूराव कूं पसंत नईं पड़ताए। इस करके वो बोला- 'ओके ब्रादर! तुमकूं अपुन रील का माफिक शॉर्ट में बताएंगा पन शांति से भेजा एंड्रेक्ट्रेक सुनने का! भड़कने का नईं। अपुन काएकूं इंडिया कूं स्पेशल आईटम बोलताए वो अबी तुमकूं क्लीयर गिरेंगा। अबी थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगा। तुम जानताए ना कि कोई बी मुलुक कूं आजादी कईसा मिला। बोले तो मारामारी करके। फरक इत्ताईच होताए कि बाकी कंट्री का पब्लिक पैले मारामारी करके शांति से रैताए, अऊर इदर अपुन का इंडिया का भाई लोग बिगर मारामारी के, बोले तो अहिंसक तरीका से प्रीडम लेके आएला अऊर अबी मारामारी करताए।'

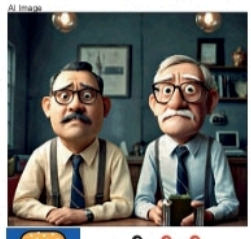

AI Image

खाली पीली

अपुन पूछेला- 'पन बाबूराव, तुम कईसा कहताए कि अपुन कूं आजादी बिगर मारामारी मिलाए? थोड़ा-भौत तो गोली-बिली चला कि नईं, भौत सा लोग जेल गएले। दंडा खाएले।' बाबूराव- 'भिड़, तुम समज के लेना कि अपुन कूं आजादी इत्ता शांति को साथ मिला कि पब्लिक कूं पताईच नईं चला कि कबी अपुन आजाद हुएले। कोई बोलताए इस तारीक कूं अपुन आजाद हुएले, कोई कैताए इस तारीक कूं। अपुन कैताए कि डेट का वास्ते जास्ती भंकसबाजी काएकूं करना! जिसकूं जबी ठीक लगताए वो पंचांग देखके अपना तारीक फिक्स करने का अऊर इंडिपेंडेंस डे मनाने का। इंडिया बोले तो आजाद मुल्क होताए। तुमकूं जो दिन ठीक लगताए उस दिन पे मनाने का।'

अपुन का दिमाग का दही जमेला इस करके उठके जाने का सोचा, तबी बाबूराव अपुन कूं सवाल किएला- 'पन तुमकूं आजादी काएकूं मांगताए?' सोच के बताने का! अबी अक्खा पब्लिक कूं तुम देखेंगा तबी क्या देखताए कि जिसकूं जो ठीक लगताए वो बोमाबोम करेंगा। टोटल फ्रीडम। तुम ए टू जेड कुछ बी बोलने कूं सकताए, कुछ बी करने कूं सकताए। तबी आजादी का जो बी डेट तुमकूं ठीक लगताए, बिंदास अपना कैलेंडर में उसकूं चिपका देने का। कोई वांदा नईं।

शेयर करें अपने अनुभव

आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें काहर nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'खाली पीली'

कांग्रेस का कन्फ्यूजन दूर

राहुल गांधी बिहार गए, तो कई महीने बाद कांग्रेस ने पटना में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, जो विशुद्ध रूप से पार्टी का था। इसमें गठबंधन के बाकी राजनीतिक दल शामिल नहीं हुए। इसका बड़ा संदेश गया। पूछा जाने लगा कि क्या कांग्रेस बिहार में एकला चलो रे की रणनीति पर आगे बढ़ेगी? दरअसल, बिहार कांग्रेस का एक वर्ग हमेशा से RJD से गठबंधन तोड़कर अपने दम पर बढ़ने का हिमायती रहा है। ऐसे में राहुल के हालिया दौरे के बाद यही चर्चा फिर से जोर मारने लगी। इस बीच RJD नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन, राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के घर जाकर किसी तरह की उलझन को दूर कर दिया। कहा जा रहा है कि राहुल ने रणनीति के तहत ऐसा किया। पार्टी नेतृत्व का मत है कि इस साल दिल्ली के अलावा सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि राज्य में अपने दम पर संगठन को खड़ा किया जा सके। साथ ही, दिल्ली के बाद अगर बिहार में भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो यह आरोप जोर पकड़ेगा कि वह I.N.D.I.A. के प्रति गंभीर नहीं है।

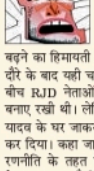

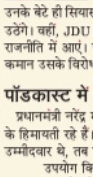

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

नीतीश के बेटे की एंट्री होगी?

बिहार में एक बार फिर सियासी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या एक और राजनेता पुत्र की सियासत में एंट्री होगी? इस बार सवाल उठ रहे हैं राज्य के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। हाल में निशांत ने एक कार्यक्रम में पहली बार सामने आकर अपने पिता और JDU के लिए वोट मांगा और राजनीतिक भाषण दिया। हालांकि पिछले कुछ बरसों में वह यदा-कदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखते रहे हैं, लेकिन कभी राजनीतिक भाषण नहीं दिया था। ऐसे में इस बार चर्चा होना स्वाभाविक था। लेकिन, सवाल यह है कि क्या खुद नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए राजनीति के दरवाजे खोलेंगे। कहा जा रहा है कि वह निशांत के राजनीति में आने के खिलाफ हैं। चूंकि नीतीश खुद परिवारवादी राजनीति के प्रबल विरोधी रहे हैं, ऐसे में अगर उनके बेटे ही सियासत में उतर गए, तो उन पर सवाल उठेंगे। वहीं, JDU का एक वर्ग चाहता है कि निशांत राजनीति में आएं। यह वर्ग नहीं चाहता कि पार्टी की कमान उसके विरोधी गुट के पास चली जाए।

पॉडकास्ट में PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद शैली में हमेशा प्रयोग के हिमायती रहे हैं। 2014 में जब वह पीएम पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया था। वह हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया में पॉडकास्ट शैली हिट हुई तो पीएम मोदी इस पर भी दिखने लगे हैं। उन्होंने पिछले दिनों नितिन कामत के साथ पॉडकास्ट किया, जो काफी हिट हुआ। उसे लाखों व्यूज मिले। इसी कड़ी में अगला नाम जुड़ा है अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन का। वह पीएम मोदी का इंटरव्यू करने खास तौर पर भारत आ रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। फ्रीडमैन दुनिया के लीडिंग पॉडकास्टर हैं। वह कई ग्लोबल हस्तियों का इंटरव्यू कर चुके हैं। तमाम दूसरे पॉडकास्टर भी इंटरव्यू के लिए कतार में लग चुके हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहने के लिए उपयुक्त समय और मौके की तलाश में रहते हैं। वैसे इतना तो तय हो गया है कि पॉडकास्ट ने अपना दबदबा स्थापित कर दिया है और पीएम मोदी के अलावा तमाम दूसरे नेता आजकल इस फॉर्मेट में इंटरव्यू देते दिख रहे हैं।

कंगना की नाराजगी

लंबी कवायद के बाद एक्टर-सांसद कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर कंगना बहुत उत्साहित थीं। अपनी पार्टी और सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिलने से वह थोड़ी नाराज भी हैं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, कंगना को उम्मीद थी कि BJP शासित राज्यों की सरकारें उनकी फिल्म को टैक्स फ्री कर देंगी। साथ ही, ठीक-ठाक प्रचार भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BJP की ओर से 'इमरजेंसी' को बहुत सीमित स्तर पर प्रमोट किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार हमेशा किसी फिल्म को प्रमोट करती नहीं दिख सकती। अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी शासित राज्यों में 'साबरमती एक्सप्रेस' को टैक्स फ्री घोषित किया गया था। लेकिन, ठीक यही तर्क कंगना की टीम की ओर से दिया गया कि जब बाकी फिल्मों टैक्स फ्री हो सकती हैं तो उनकी फिल्म क्यों नहीं हो सकती?

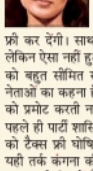

BJP में बदलाव

कुछ दिनों में BJP संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इससे पहले कई राज्यों के पार्टी अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसे लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी है। तमाम नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको या उनके गुट के नेताओं को अधिक से अधिक तरजीह मिले। इसी कोशिश में बात इतनी बढ़ जा रही है कि कई राज्यों में पार्टी को दिक्कत भी हो रही है। मिसाल के तौर पर बिहार को लें तो पिछले हफ्ते वहां BJP की एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आपसी खींचतान को समाप्त करने के लिए अभी इस बैठक की तारीख को आगे बढ़ाया गया है।

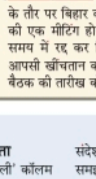

AI Image

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

खुलेंगे नए अवसर

20 जनवरी का लेख 'क्या भारत के बिना ट्रंप का काम चलेगा' पढ़ा। डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। ट्रंप की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की व्यापार नीतियों में protectionism और उच्च टैरिफ की प्राथमिकता है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा वीजा नीतियों में बदलाव से भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अमेरिका में काम करना और पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप की नीतियों की बदौलत भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर भी खुल सकते हैं।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

संकल्पों की गंभीरता

7 जनवरी को 'खाली पीली' कॉलम में प्रकाशित लेख 'रिजोल्यूशन का पहेंसा नई लगताए' बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक लहजे में नए साल के संकल्पों पर टिप्पणी करता है।

खाली पीली

लोग नए साल में कुछ बड़ा करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन संकल्पों को ज्यादा समय तक नहीं निभा पाते। बाबूराव के माध्यम से लेखक संदेश देते हैं कि हमें इन संकल्पों को समझदारी से लेना चाहिए।

शैलजा सक्सेना, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

Tik Tok बैन पर नरम पड़े ट्रंप
- एक खबर
- कहीं ट्रंप का कोई 'हिडेन अजेंडा' तो नहीं।

सुरेंद्र यादव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

सफलता का बीज आपके अंदर, उसे अंकुरित होने दें

प्रेम रावत जी

बनाने वाले ने आपके अंदर एक चाह डाली है। वह चाह है परमानंद की। हरेक मनुष्य को उस आनंद की जरूरत है। मनुष्य की सारी प्यास बुझ जाए, तो भी एक प्यास बनी रहती है। वह है, जीवन को सफल कैसे करें।

क्या आपको मालूम है कि रेगिस्तान में भी बीज होते हैं? रेत के अंदर सालों-साल पड़े रहते हैं। वे इंतजार करते हैं बारिश का। कई बार बारिश नहीं आती, पर बीज अपना मकसद भूल नहीं जाता। उसको अपना मकसद याद है और अगर एक साल बारिश नहीं आई, तो भी कोई बात नहीं। बीज उतना ही तैयार है, जितना पिछले साल था। और अगर दो साल बारिश नहीं आई, तो भी कोई बात नहीं, वह अपनी तैयारी नहीं बदलता। मनुष्य होता तो कहता, 'अरे! दो साल बारिश नहीं आई, अब तीसरे साल क्या आएगी! मैं कुछ नहीं करूंगा।' लेकिन, बीज अपनी तैयारी नहीं छोड़ता। जब भी बारिश आए, वह तैयार है उगने के लिए। उसका जो काम है, उसे वह करता है। रेगिस्तान में हरियाली लेकर आता है। लेकिन, इंसान ऐसा नहीं कर पाता।

आपके अंदर भी अपने जीवन को सफल बनाने का बीज है। जब भी ज्ञान की बारिश होगी, तब वह बीज उपजेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान आपके सच्चे स्वरूप को महसूस करने का तरीका है। एक तरफ हृदय है, वह आनंद है और दूसरी तरफ है सारी दुनिया। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर असत्य। एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ अज्ञान। एक तरफ परम स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ माया-मोह का जाल। एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख। एक तरफ पीड़ा है, दूसरी तरफ परमानंद। एक तरफ प्यार है और एक तरफ नफरत। इस दुनिया के हर जीव को मोह-माया अपनी अपनी तरफ बुलाते हैं। उसे फंसाने की कोशिश करते हैं कि, 'तू ऐसा कर, ऐसा समझ तो तुझे सुख मिलेगा, तुझे आनंद मिलेगा।' लेकिन दूसरी ओर सिर्फ हृदय है, जो बिना शब्दों वाली भाषा बोलता है और जिसे सभी लोग नहीं समझ सकते। इसमें सिर्फ कृपा महसूस होती है और महसूस होता है उससे जुड़ा आनंद।

हम सभी मनुष्यों के जीवन में तीन पन्ने ही परमपिता परमेश्वर से मिले हैं। पहला है जन्म, दूसरा जीवन और तीसरा मृत्यु। पहला और आखिरी पन्ना खुद परमपिता परमेश्वर ने लिखा है। इन दोनों पर हम कुछ नहीं लिख सकते। अब एक पन्ना बचता है जीवन का। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस पन्ने पर हम क्या लिखना चाहते हैं और क्या नहीं। ज्ञान ऐसी विधि है, जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं।

प्रस्तुति : आर. डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

नभ टाइम्स, नई दिल्ली, 21 जनवरी 2025 (नवभारत टाइम्स) | प्रिंटर, प्रकाशक और मुद्रक [illegible] द्वारा प्रकाशित [illegible] मुद्रित। प्रिंटिंग प्रेस [illegible] से मुद्रित। प्रकाशन स्थल [illegible] से प्रकाशित। प्रधान संपादक [illegible] (प्रधान कार्यालय: टाइम्स हाउस, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में प्रकाशित तथा **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत** का **अंग्रेजी दैनिक नभ टाइम्स** और **नवभारत** और नवभारत टाइम्स, सेक्टर 62, नोएडा-201 309, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजधानी, लखनऊ, प्रकाशन से मुद्रित। फोन : 2102222222 फैक्स: 2102222222, संपादक कार्यालय : (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दूरभाष-2102211) जिला क्षेत्र मुद्रण : 1. श्री. आर. जोशी / नेतृत्व में मुद्रण : ओसवाल प्रिंटर्स, दिल्ली 2. के. ... दिल्ली, 3. ... संपादक (प्रिंटर्स नवभारत) : आलोक पांडे (इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के लिए हमें संपादक दि. पै.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

विश्व राजनीति का बड़ा हिस्सा मौलिक संघर्ष में निहित है, पर इसे समझदारी से लड़ा जाना चाहिए। -जबिग्न्यू ब्रेजिंस्की

बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए, बल्कि समग्र विश्व के लिए एक नए दौर के आरंभ का प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) में संबंध अलग ऊंचाई पर पहुंचेंगे।

वही ट्रंप, नई उम्मीदें

डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के सैंतालीसवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए, बल्कि समग्र विश्व के लिए एक नए दौर के आरंभ का प्रतीक है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर छाप छोड़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी पुनर्परिभाषित किया था। हालांकि उनके वर्तमान कार्यकाल को लेकर तमाम तरह की अनिश्चितताएं जताई जा रही हैं, उनके विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता चुके हैं, लेकिन इन सबके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत और दुनिया भर में उनके आगमन को लेकर दिखा उत्साह यह तो बताता ही है कि उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है, इससे उन उम्मीदों की भी झलक मिलती है, जो उनसे लगाई जा रही हैं। इन सबके बीच उन्होंने अपने पहले सौ फैसलों का ब्लूप्रिंट रखा है, लेकिन इनका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती तो बीजिंग पर काबू पाने की होगी, जिसका तेज उभार अमेरिका की एकध्रुवीयता के लिए खतरा बन सकता है। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो को विदेश मंत्री और माइकल वाल्ट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने से, जो दोनों ही चीन विरोधी और भारत समर्थक हैं, ट्रंप की भावी नीतियों की दिशा को समझा जा सकता है। लेकिन, चीन व दूसरे देशों पर भारी आयात शुल्क संबंधी उनके इरादे बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर व्यापार युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में शैतानियत की धुरी माने गए देशों में शामिल ईरान भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वहां अशांति होगी, तो अमेरिका को पश्चिम एशिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति रखनी होगी, जिससे वह अपनी पूरी ऊर्जा चीन से निपटने में नहीं लगा सकेगा। इस्राइल-हमास युद्धविराम में ट्रंप की भूमिका से कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन रूस-यूक्रेन जंग को रोक पाने की चुनौती अब भी है, जिसके लिए उन्हें शायद अलग स्तर की कूटनीति दिखानी होगी। जहां तक बात भारत की है, तो समझने वाली बात है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते महज सरकारों के बीच की बात नहीं, बल्कि बहुपक्षीय हैं। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर सौ फीसदी टैरिफ की चेतावनी भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। ट्रंप की यही अप्रत्यासितता कई बार अनिश्चितता का कारण बन जाती है, लेकिन यह भी है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व पर अंकुश लगाने की रणनीति में उन्हें भी भारत की जरूरत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों, बल्कि वैश्विक शांति व स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी।

अमेरिकी नीति के केंद्र में बना रहेगा भारत

अमेरिका में ट्रंप के युग की शुरुआत हो गई है। उनको लेकर तमाम वैश्विक अनिश्चितताएं गढ़ी जा रही हैं। लेकिन भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में ट्रंप-मोदी के गर्मजोशीपूर्ण संबंधों के अलावा भी कई पहलू हैं, जिनकी ट्रंप भी अनदेखी नहीं कर सकते।

सुरेंद्र कुमार
पूर्व राजदूत

डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हों या दुश्मन, दोनों ही पिछले कुछ वक्त से उनके द्वारा दिए गए बयानों से उत्तेजना महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को भी अपनी यही छवि पसंद है। वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर अमेरिका की खाड़ी रखने और ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने जैसी तमाम बातें कह चुके हैं।

जाहिर है कि पूरी दुनिया में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर एक अनिश्चितता व बेचैनी जैसा माहौल है, लेकिन इन सबके बीच जो एक देश आश्वस्त हो सकता है, वह भारत ही है। हालांकि, भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने, अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने की धमकी और एच1बी वीजा के अनुदान को कड़ा करने संबंधी कुछ प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत न होने की कुछ वजहें हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट में दोनों दलों का समर्थन जारी है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका के अपने कथित रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप को पता है कि भारत के अलावा दूसरा कोई ऐसा देश नहीं है, जो चीन का मुकाबला कर सके, जिसने पड़ोसियों के खिलाफ अपने आक्रामक रुख को कम नहीं किया है और न ही दक्षिण चीन सागर में अपने एकतरफा दावों को छोड़ा है।

तथ्य यह भी है कि हिंद-प्रशांत, क्वाड, जी-20, आई2यू2 व आईएमईसी और ओपचार्जिक सहयोगी नहीं होने के बावजूद जब भी जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया भारत सहयोगी साझेदार रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार में तेजी आ रही है; भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पास बड़े भंडार हैं, जिससे अमेरिकी रक्षा निर्माण कंपनियों को बड़े अनुबंध मिलेंगे, नौकरियां पैदा होंगी और ट्रंप खुश रहेंगे। अगर ट्रंप ज्यादा अमेरिकी रक्षा निर्माताओं को भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो रक्षा संबंध और भी गहरे हो जाएंगे, जैसे कि तकनीक हस्तांतरण के साथ जीई ने एचएएल के साथ जीई एफ 414 जेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया है, जो बाइडन के कार्यकाल में हुआ था। अगस्त, 2024 में हस्ताक्षरित दो समझौती-आपूर्ति सुरक्षा समझौता (एसओएसए) और संपर्क अधिकारी नियुक्ति समझौता (एलएओ) से भी रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के अनुसार, 2023-24 में, 118.2 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, और भारत के पक्ष में 36.8 अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा, जो भारत के वैश्विक व्यापार का 17 फीसदी हिस्सा है। हालांकि, भारत को स्वेच्छा से कुछ चुनिंदा आयातों पर शुल्क कम करना चाहिए; कई उत्पादों पर हमारी शुल्क दरें आसियान देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों से बहुत अधिक हैं। बदले में, हमें कई भारतीय निर्यातों के लिए बहुत आसान बाजार पहुंच की मांग करनी चाहिए। वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा के साथ भारत को ट्रंप द्वारा पहले कार्यकाल के दौरान खत्म की गई जीएसपी व्यवस्था की बहाली की मांग नहीं करनी चाहिए। पहले कार्यकाल में उनके दबाव के कारण ही हमने ईरान से तेल आयात बंद कर अमेरिका से तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे भारत का निर्यात बढ़कर 14.3 अरब डॉलर हो गया है; उनके दूसरे कार्यकाल में इस व्यापार के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

बाइडन के राष्ट्रपतित्व काल में भारतीय और अमेरिकी एनएसए द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (आईसीईटी), दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग का प्रेरक इंजन बनने जा रहा है, क्योंकि यह वायरलेस दूरसंचार, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है और सरकारों, उद्योगों, शिक्षाविदों, स्टार्टअपों को एक मंच पर लाता है। भारत को ट्रंप 2.0 के तहत और अधिक समझौतों की आवश्यकता है, जैसे कि बाइडन के नेतृत्व में चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर निर्माण समझौते किए गए थे। सबसे बढ़कर, 40 लाख सशक्त, अमीर और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत पुल का निर्माण करते हैं। ट्रंप पारंपरिक राजनेताओं के किसी भी सांचे में फिट नहीं बैठते हैं। वह एक अरबपति से राजनीतिज्ञ बने, राष्ट्रपति बने। उनकी धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन यही तो उनकी शैली है। ट्रंप अपने भड़काऊ बयानों से अपने समकक्षों को परेशान करते हैं और उन्हें सौदे करने के लिए मजबूर करते हैं। अपने पहले कार्यकाल में, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ उनकी शुरुआती धमकियों ने उन्हें संशोधित नाफ्टा पर सहमत होने के लिए मजबूर कर दिया था। और चीन भी अमेरिकी निर्यात को चीन में आने देने के लिए सहमत हो गया।

अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत अरुण के सिंह को लगता है, 'वह अपने दोस्तों, भागीदारों और कमजोर देशों को धमकाते रहे हैं और ताकत का दिखावा भी करते रहे हैं।' सीभाग्य से, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ उन्होंने व्यक्तिगत गर्मजोशी वाला तालमेल विकसित किया है। 'हाउडी मोदी' (सितंबर 2019) भारतीय अमेरिकियों का सबसे बड़ा समागम था, जिसमें कभी ट्रंप ने भाग लिया था। यह देखना आश्चर्यजनक था कि एक भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में 50,000 लोगों की भीड़ के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति का परिचय करा रहे थे। और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मोदी द्वारा आयोजित नमस्ते ट्रंप (फरवरी 2020) एक कदम और आगे बढ़ गया। 1,25,000 भारतीयों ने ट्रंप का ऐसा स्वागत किया, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। फिर आगरा में ताजमहल के लॉन में मेलानिया के साथ सैर ने उनके लिए शायद जीवन भर की यादें छोड़ दी होंगी। ट्रंप के फंडे स्पष्ट हैं : जो लोग अमेरिका से कुछ चाहते हैं, उन्हें कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए, हमें सौदेबाजी और समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने खुद कहा था कि वह एक सख्त वार्ताकार हैं! और मोदी का मानना है कि सबसे अच्छा सौदा वह होता है, जिसमें दोनों पक्ष विजेता महसूस करते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

थॉमस मान

ट्रेन दुर्घटना के बाद अव्वल दर्जे का टिकट किसी काम का नहीं बचा था। बचाव के लिए आई ट्रेन में भी जमींदार अपना रोब दिखाने लगे। बुजुर्ग ने उन्हें हिदायत दी कि बैठने को जगह मिल रही है, यह भी क्या कम है।

अकड़ हर जगह नहीं चलती

दो साल पहले की बात है, मैं एक ट्रेन से सफर कर रहा था, जो बाद में एक दूसरी ट्रेन से टक्कर खाकर उलट गई। वह घटना मुझे पूरी तरह से याद है। रात को नौ बजे म्यूनिख स्टेशन से ड्रेसडेन की ट्रेन छूटती थी। चारों तरफ बेहद भीड़ थी। यानी, कुली और सामानों से प्लेटफार्म भरा था। एक टिकट चेकर एक बूढ़े के पीछे दौड़ा। उसने तीसरे दर्जे का टिकट लेकर ऊंचे दर्जे की गाड़ी के प्रावदान पर पैर रखा था। एक सज्जन मेरे सामने चहलकदमी कर रहे थे। उनके साथ एक छोटा-सा खूबसूरत कुत्ता था। उसके गले में चांदी की जंजीर थी। वह आदमी कोई अमीर जमींदार मालूम हो रहा था। टिकट चेकर बड़े अदब से सलाम करके बातें कर रहा था। वह सज्जन मेरे बगल वाले डिब्बे में चढ़े। मेरे शरीर में उनकी कुहनी से धक्का लगा, मगर उन्होंने सज्जनता के खयाल से दुख प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा। मैं कुछ आश्चर्य से देखने लगा, मगर उन्होंने मुझको और भी चकित करके, सोने के कमरे में प्रवेश किया। सभी जानते हैं कि कुत्ता लेकर सोने के कमरे में जाना अनुचित है, कानून के खिलाफ है। मगर उन्होंने परवाह नहीं की।

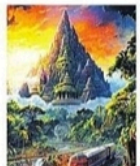

सीटी बजी और ट्रेन चलने लगी। मैं रोशनी के नीचे एक किताब लेकर बैठ गया। टिकट चेकर आकर खड़ा हो गया। मैंने टिकट निकाल कर उसको दिखलाया। फिर 'शुभरात्रि' कहकर वह जमींदार के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। कई बार खटखटाने के बाद भीतर से क्रोधभरी आवाज आई, 'रात को कौन मुझे टिक कर रहा है?' टिकट, चेकर बहुत विनय के साथ कहने लगा, उसका आवश्यक कर्तव्य है, इत्यादि। चेकर ने टिकट देखा, क्षमा-प्रार्थना करके चला गया। सोने जा ही रहा था कि ट्रेन की टक्कर हो गई। यह घटना मुझे बिल्कुल तस्वीर की भांति याद है। सहसा बज्रपात की तरह एक भयानक आवाज हुई और जोर का धक्का लगा। मैं उछलकर बेंच से दूर जा गिरा। फिर ट्रेन उलट गई, शायद यात्रियों के आर्त स्वर ने परमात्मा को जागृत कर दिया था। ट्रेन रुक गई। इसके बाद बाहर निकलने के लिए दौड़-धूप, हल्ला, धक्का-मुक्की होने लगी। कब और किस तरह से मैं ट्रेन से निकलकर खुले मैदान में जाकर खड़ा हुआ, यह ठीक याद नहीं। उस समय जोर से चक्कर आ रहा था। एक विशाल मरे हुए दैत्य की भांति ट्रेन उलटकर पड़ी हुई थी। हम सब के सब राहत गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे रहे। साहित्यिक, राजनीतिक, गरीब, मजदूर अनेक के साथ मेरा परिचय हो गया। ट्रेन आ गई। जिसने जो डिब्बा पाया उसी में चढ़ गया। किसी तरह डिब्बे में जाकर एक कोने में बहुत कठिनाई के साथ जगह बनाकर बैठ गया। फिर अपने सामने वही जमींदार, जो कुत्ता लेकर ट्रेन में सवार हुए थे। उनके बैठने की जगह बहुत तंग थी। अब उनका अव्वल दर्जे का टिकट किसी काम का नहीं था। आकस्मिक परिस्थिति के सामने छोटे-बड़े का विभेद बिल्कुल गायब हो गया था। वह बड़े तीव्र शब्दों में इस तरह के साम्यवाद के विरुद्ध टिप्पणी करने लगे। एक बुजुर्ग, जो उनके सामने बैठा था, बोला-'जनाब! बैठने के लिए जगह मिली है, यही गनीमत समझिए।

विनम्रता को अपनाएं

सूत्र

जीवन के लिए जैसे हवा और पानी की जरूरत है, उसी प्रकार विनम्रता की जरूरत है। विनम्रता वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको तरोताजा और नया बनाए रखती है। घमंड हमें कृत्रिम बनाता है और विनम्रता हमें वास्तविक बनाती है। वास्तविक प्रतिभा और कुछ नहीं, बल्कि विचार के क्षेत्र में विनम्रता का अलौकिक गुण है।

दूसरा पहलू

पटियाली में खड़ी बोली के अप्रतिम कवि अमीर खुसरो के सम्मान में बना था पुस्तकालय, अब यहां हैं रैन बसेरा।

जन्मस्थान में ही भुला दिए गए तूती-ए-हिंद

सर्दी की अलसाई दोपहर में उस टीले से दूर तक नजर जाती है। धूल भरी सड़क और दोनों तरफ सरसों के खेत...यही है पटियाली। 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान की सेना के काफिले ने जब इस जगह को कुछ वक्त गुजारने के लिए चुना, तो कौन जानता होगा, यहां ऐसे दिग्गज का जन्म होगा, जिसको तूती पूरी दुनिया में गूंजेगी। यही है तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले की तहसील पटियाली। लेकिन अब यहां ऐसा कुछ भी नहीं, जिसे इस अजीम शख्सियत से जोड़कर देखा जा सके।

भूपेंद्र कुमार

आखिर क्या था खुसरो में जो उन्हें खास बनाता है? पटियाली निवासी शोएब बताते हैं कि खुसरो ही थे, जो परमात्मा को प्रियतम की तरह चाह सकते थे। तहसील टीले पर बसी है। कभी यह किला रहा होगा, जहां खुसरो का जन्म हुआ। आज उनकी याद में केवल एक पार्क व पुस्तकालय है, वह भी अब रैन बसेरा बना दिया गया है। दीवारों पर खुसरो के कलाम हैं और जानकारी भी है, पर सब अधी-अधूरी। एक में *सुलतायी* फिल्म के पूरे गीत को ही उनका बता दिया गया है, जिसकी पहली दो पंक्तियां उनकी लिखी हैं। कुछ वर्ष पहले तक 27 दिसंबर को उनके जन्मदिवस पर आयोजन होते थे, अब नहीं होते। हिंदवी (13वीं सदी में मध्य भारत की बोली) में खुसरो के योगदान के लिए अतीत के पन्ने पलटने होंगे। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्क मध्य एशिया की लाचन जनजाति के थे।

मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के अत्याचारों से त्रस्त होकर वह दिल्ली आ गए और शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की सेना में शामिल हो गए। उनकी मां का नाम दौलत नाज था। खुसरो के पिता बंगाल के लिए सैन्य अभियान पर जाते समय पटियाली में कुछ समय रुके थे। यहीं 1252 ईस्वी में खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो आठ साल की उम्र में दोहे लिखने लगे थे। एक सैन्य अभियान में उनके पिता की मृत्यु हुई, तो वह दिल्ली अपने नाना नवाब इमादुल मलिक के पास रहने लगे। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को वह अपना गुरु मानते थे। उन्होंने दिल्ली के आठ सुल्तानों का शासन देखा। खुसरो की पहेलियां आज भी ग्रामीण अंचलों में सुनाई देती हैं। 1325 ईस्वी में उनका निधन हो गया और उन्हें निजामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में दफनाया गया। शोएब खुसरो की याद में बने पुस्तकालय के बगल में मौजूद मस्जिद और रामलीला मैदान व मंदिर को दिखाते हैं। कहते हैं, यहां सब मिलजुलकर रहते हैं, यही तो सामाजिक समरसता का वह ताना-बाना है, जिसके लिए खुसरो याद किए जाते हैं।

खुसरो आठ साल की उम्र में दोहे लिखने लगे थे। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को वह अपना गुरु मानते थे। उन्होंने दिल्ली के आठ सुल्तानों का शासन देखा। खुसरो की पहेलियां आज भी ग्रामीण अंचलों में सुनाई देती हैं।

आंकड़े

पर्याप्त नींद

भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग चैन से नहीं सो पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारतीय पर्याप्त नींद लेते हैं।

आंकड़े संबंधित देशों में पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों के, प्रतिशत में | स्रोत : Ipsos

काक होने का शाप मिलने के बाद भी जब ब्राह्मण विचलित नहीं हुए, तब लोमश ऋषि ने उन्हें राम नाम का मंत्र देकर बालकराम का ध्यान करने का उपदेश दिया।

काकभुशुंडि को मिला राम मंत्र

अंतर्धारा
संकलित

काकभुशुंडि जी पूर्व जन्म में अयोध्या के निवासी थे। कालांतर में वह उज्जैन आ गए, लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करने पर उन्हें भगवान शंकर ने शाप दे दिया। लेकिन उनके गुरु ने आराधना कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने कहा, इसे शाप भोगते समय कष्ट नहीं होगा और अंत में भगवान राम की भक्ति प्राप्त होगी।

कई योनियों में जन्म लेने के बाद अंत में उन्हें ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई। वह हमेशा भगवान के संबंध में ही प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन वह सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि के पास पहुंचे। लोमश ऋषि ने उन्हें निर्गुण उपदेश दिया, जिसका काकभुशुंडि जी ने चार-बार खंडन किया। लोमश ऋषि ने उन्हें काक (कौवा) होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर भी वह विचलित नहीं हुए। उनकी समता और भगवदभक्ति देखकर लोमश ऋषि प्रसन्न हुए और काकभुशुंडि जी को अपने पास बुलाकर राम नाम के मंत्र का उपदेश दिया। लोमश ऋषि ने उन्हें बालकराम का ध्यान करने के लिए कहा और कुछ दिन तक अपने पास रखकर भगवान राम की गुप्त लीलाओं का वर्णन किया। अंत में लोमश ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम ज्ञान-वैराग्य के समुद्र, इच्छामृत्यु एवं कामरूप हो जाओगे, जहां रहोगे वहां एक योजन के आसपास अज्ञान, काल, काम और उसके परिणाम नहीं आ सकेंगे। इसके बाद गुरु आज्ञा लेकर वह नीलाचल पर्वत पर निवास करने लगे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 अक्तूबर, 1963

वार्ता विफल हुई तो केन्या खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा

वार्ता विफल हुई तो केन्या अपने को स्वतंत्र घोषित कर देगा

केन्या के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुअ्बी ने घोषणा की है कि यदि लंदन में हो रही केन्या सांविधानिक वार्ता सफल नहीं होती, तो केन्या छह दिन में स्वतः अपने को स्वतंत्र घोषित कर देगा।

आखिर कहना क्या चाहती हैं दीदी

राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए एक राज्य की मुख्यमंत्री अगर बीएसएफ पर ही घुसपैठ के आरोप लगाए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

विमल राय

सुरक्षा

आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के 'असली स्वतंत्रता' वाले बयान को ममता बनर्जी ने देशद्रोह कहा है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर घुसपैठ का आरोप लगाकर क्या वह राष्ट्रविरोधी बयान नहीं दे रही हैं? पश्चिम बंगाल जैसे सूबे की मुख्यमंत्री अगर कहें कि बीएसएफ राज्य में घुसपैठ करवा रहा है, तो इसे हल्के में नहीं ले सकते। यह कथन भारत के लोकतंत्र की परीक्षा लेने वाला है। हालांकि बंगाल में चुनावी हिंसा और पक्षपाती शासन की वजह से स्थितियां पहले से ही नाजुक हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया बयान हमारे बहादुर सैनिकों का अपमान है।

बंगाल की सीमा भी ऐसे देश से लगी है, जो अब भारत को अपना दुश्मन मानने का दुस्साहस कर रहा है। पहले तो वहां भारतीय सामानों के बहिष्कार की हवा बनाई गई और फिर तख्तापलट हो गया। जेल से हजारों आतंकियों की रिहाई के बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ। अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पड़ाचार और पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती ने ढाका के इरादे साफ कर दिए हैं। इन हालात में चाहिए था कि मुख्यमंत्री ममता असम और त्रिपुरा सरकारों की तरह सीमा पर बीएसएफ की मदद में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी झोंकतीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह उल्टे बीएसएफ पर आरोप लगा रही हैं।

बांग्लादेश से लगी बंगाल की सीमा 2,216 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से करीब 20 फीसदी हिस्से में बाड़ नहीं है। कई जगह नदियों को बॉर्डर माना गया है। इस लेखक ने स्वयं उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर का दौरा किया था और देखा था कि गर्मी के दिनों में उस नदी को पैदल ही पार किया जा सकता है। बीएसएफ की चौकसी के बावजूद रात में घुसपैठ के अलावा ड्रग, सोना, चीनी, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी होती है। आरोप लगाने से पहले ममता को यह बताना चाहिए था कि कम से कम 72 स्थानों पर बीएसएफ की चौकियां बनाने के लिए जमीन देने में सरकार क्यों विफल है? सीमावर्ती गांवों के लोगों से अदालतों में फर्जी दीवानी मुकदमे क्यों करवा दिए जाते हैं? इसके अलावा भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है। घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ स्थानीय पुलिस को सौंप देती है। उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और ज्यादातर मामलों में पुलिस जमानत का विरोध नहीं करती है। जमानत पाकर वे स्थानीय नेताओं और दलालों की शरण में जाते हैं, जो उन्हें आधार, वोटर कार्ड आदि बनवाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह हर साल हजारों बांग्लादेशी भारतीय नागरिक बन दिए जाते हैं।

सवाल है कि सीमा को असुरक्षित रखने के पीछे के राजनीतिक स्वार्थ और बीएसएफ के खिलाफ जघन्य आरोप लगाकर कोई कानून के दायरे से बाहर कैसे रह सकता है? आली रानी सरकार नामक बांग्लादेशी महिला तृणमूल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ती है। रशीदाबाद ग्राम पंचायत की मुखिया लवली खातून भी बांग्लादेशी है, जो तृणमूल में शामिल होकर पंचायत चुनाव जीती है। ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं। पिछले साल 28 दिसंबर को बांग्लादेशियों के लिए अवैध रूप से पासपोर्ट बनवाने के खेल का खुलासा हुआ, जब उत्तर 24 परगना के गायघाटा में मास्टरमाइंड मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। रैकेट में शामिल एक पूर्व पुलिसकर्मी अब्दुल हई तीन जनवरी को इसी जिले के कमरपुर से गिरफ्तार हुआ। उसके बैंक खाते से अवैध कमाई के 12.5 लाख रुपये बरामद हुए। यह गिरोह आधार कार्ड के लिए 15 हजार, वोटर आईडी कार्ड के लिए 10 हजार, जन्म प्रमाणपत्र के लिए 12 हजार और पैन कार्ड के लिए 3,000 रुपये वसूल रहा था। पूरे घोटाले के संबंध में उत्तर 24 परगना के बारासात कोर्ट के लॉ क्लर्क समीर दास सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने माना है कि ट्रैवल एजेंसी की आड़ में संचालित यह रैकेट घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से 73 फर्जी पासपोर्ट जारी करवा चुका है। सवाल है कि बिना उचित सत्यापन किए ये पासपोर्ट कैसे जारी हो गए?

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जेल से छूटे आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। बंगाल के विशेष कार्य बल और असम पुलिस ने 18 और 30 दिसंबर को मुर्शिदाबाद से प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पहले असम में जेएमबी के तीन आतंकी पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ के बाद मुर्शिदाबाद में स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले आतंकियों के ठिकाने का पता चला। 18 जनवरी को मालदा जिले के वैष्णवनगर सीमा के पास बाड़ लगा रहे बीएसएफ जवानों व स्थानीय लोगों पर दो बम फेंके गए, जिसमें दो जवान घायल हो गए। त्रिपुरा सीमा पर भी बांग्लादेशी उग्रवादियों ने एक बीएसएफ जवान से बंदूक छीनने की कोशिश की। 18 जनवरी को ही बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा।

सम्पादकीय

दूसरे देशों में जाकर संकट में फंस रहे भारतीय, विदेशी युद्धों के दौरान हो रही कत्लेआम की पीड़ा

अक्सर अनधिकृत रूप से, चोरी-छिपे या गलत दस्तावेजों और चालबाज बिचौलियों की मार्फत परदेस पहुंचे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर वैसी स्थिति में जब वैसे देशों के बीच युद्ध छिड़ा हो, जहां वे बाहर से गए हों तो उसकी मार अलग से झेलनी पड़ती है। कई लोग नाहक ही मारे जाते हैं। ऐसे समय में भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए उन्हें वहां से निकालना कठिन काम हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे ऐसे ही लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय काफी समय से जद्दोजहद कर रहा है। अभी मंत्रालय ने कहा है कि वहां रूस-यूक्रेन मोर्चे पर अब तक बारह भारतीय मारे जा चुके हैं, सोलह लापता हैं, एक का इलाज चल रहा है। कुछ महीने पहले पता चला कि बिचौलियों के जरिए भारत से बड़ी संख्या में ऐसे युवक रूस गए हैं, जिन्हें भर्ती तो किसी और काम के लिए किया गया था, मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा कर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में भेज दिया गया। जब उनके परिजनों को इस बात की खबर मिली, तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से वापस लाने की गुहार लगाई। जांच से पता चला कि ऐसे एक सौ छब्बीस युवकों को जंग में झोंक दिया गया था। विदेश मंत्रालय की अपील पर रूस सरकार ने छियानबे भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया।

ऐसे मामले अन्य देशों में भी देखे जा चुके हैं। रोजगार की तलाश में बहुत सारे युवा अनधिकृत रूप से दूसरे देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों से तो इस तरह अनधिकृत प्रवेश करने वाले अनेक लोगों के मारे जाने की खबरें भी आती हैं। खाड़ी देशों में भी इसी तरह बहुत सारे युवक जाते और वहां बंधक बना लिए जाते हैं। इन मामलों के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपील करती रहती है कि विदेश जाते समय अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आपके बारे में यहां सही-सही जानकारी उपलब्ध रहे और किसी संकट के समय वहां से निकालना आसान हो। बिचौलियों और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से भी सावधान करती रही है, मगर हकीकत यह है कि हर वर्ष हजारों लोग इस अपील को धता बताते हुए विदेश जाने का प्रयास करते हैं। इसकी वजहें सरकार को भी पता हैं और यह भी छिपी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की खाहिशों का लाभ उठाने वाले बिचौलियों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा। जब पंजाब में 'कबूतरबाजी' के बढ़ते मामले प्रकाश में आए थे, तब सरकार ने ऐसे बिचौलियों पर अंकुश लगाने की पहल की थी, मगर वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। यह भी विचार करने का विषय है कि क्यों हमारे देश से बड़ी संख्या में युवा विदेश का रुख करते हैं। यह केवल ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके युवाओं के साथ नहीं है, छोटे-मोटे काम की चाह में भी बहुत सारे युवा दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। सब जानते हैं कि यहां रोजगार के पर्याप्त अवसर और आमदनी का साधन न होने के कारण, थोड़ी बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए लाखों युवा हर वर्ष ऐसे देशों में भी जाने का प्रयास करते हैं, जहां कोई खास कमाई के अवसर नहीं हैं।

थोड़े संपन्न माने जाने वाले देशों में प्रवेश पाने के लिए तो मुंहमांगी रकम खर्च करने को तैयार देखे जाते हैं। अच्छी बात है कि सरकार दूसरे देशों में संकट में फंसे लोगों को वापस लाने के संजीदा प्रयास करती है, मगर जब तक रोजगार के मोर्चे पर मुसीदी नहीं दिखेगी। लोग परदेस में पीड़ा झेलने को मजबूर होते रहेंगे।

आज का इतिहास — बढ़ता राजस्थान

21 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- स्टॉकहोम संधि पर पर्सिया और स्वीडन ने 1720 में हस्ताक्षर किए।
- विलियम हिल ब्राउन की पुस्तक 'द पॉवर ऑफ सिम्पथी' बोस्टन में 1789 में छपी थी।
- अंग्रेजी वर्णाक्षर टेलीग्राफ का पेटेंट विलियम कूक और चार्ल्स व्हीलस्टोन को 1840 में दिया गया था।
- लिफाफे मोड़ने वाली मशीन का पेटेंट रसेल हावेस ने 1853 में करवाया था।
- 1865 में आज ही के दिन पहली बार एक तेल के कुएँ को तारपीडो से ड्रिल किया गया था।
- ब्रिटेन में 1924 में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसमें रैम्जे मैक्डोनाल्ड बने प्रधानमंत्री।
- अल्बानिया ने खुद को 1925 में गणराज्य घोषित किया।
- कॉपीराइट अधिनियम 1958 को लागू किया गया।
- असम का नेफा क्षेत्र (नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) 1972 में केन्द्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना।
- 1981 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया।
- इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास 1996 में यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई।
- हांगकांग में सन 2000 में एशिया के प्रथम 'स्लिट लिवर' का प्रत्यारोपण हुआ।
- चालक रहित अमेरिकी टोही विमान 2003 में पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त।
- भारत ने 2008 में इस्राइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर आर्बिट में स्थापित किया।
- वर्ष 2007 का 'हाल आफ फेम अवार्ड' की लिस्ट में 2008 को पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया।
- कर्नाटक के बीदर में 2009 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्यकिरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

21 जनवरी को जन्मे व्यक्ति

- 'ए मैन ऑफ ऑल सीजन' 'क्वीज शो', जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कोफील्ड का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ।
- उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ।
- पश्चिम भारतीय संगीतकार बिली ओशन का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ।

21 जनवरी को हुए निधन

- 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु।
- 1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु।
- 1950 में अंग्रेजी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु।
- 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष की मृत्यु।

विशेष आलेख

विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय ही 'सनातन धर्म'

— पंडित तारा चंद

आज विश्व में सनातन धर्म की व्याख्या को लेकर अपने - अपने तर्क है, लेकिन यह सर्वविदित है कि हिन्दू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र सोलह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे 'सनातन धर्म' भी कहा जाता है। मां कामाख्या ज्योतिष शोध संस्थान, सवाई माधोपुर के अध्यक्ष पंडित तारा चंद शास्त्री बताते है कि बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिन्दू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नही, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है।

राकेश शर्मा

पंडित तारा चंद शास्त्री के मुताबिक महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र सोलह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। जो निम्नानुसार है -

1. **गर्भाधान** - महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भधारण के लिए आश्यक है इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थ्यता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान-संस्कार करना होता है।
2. **पुंसवन** - पुंसवन संस्कार तीन महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में तीन महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है, इसका उदाहरण है अभिमन्यु जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी।
3. **सीमंतोन्नायन सीमंतोन्नायन** संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और आठवें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए मां उसी प्रकार आचार-विचार, रहन-सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए।
4. **जातक्रम** - बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो।
5. **नामकरण** - जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे की इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं जो कि गलत है।
6. **निष्क्रमण** - इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे।
7. **अन्नप्राशन** - अन्नप्राशन संस्कार संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6-7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है।
8. **चूड़ाकर्म** - सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं, तब वह चूड़ाकर्म या मुण्डन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु एक वर्ष हो जाती है तब या तीन वर्ष की आयु में या पांचवें या सातवें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है।
9. **कर्णवेध** -कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके पांच कारण हैं, एक- आभूषण पहनने के लिए। दूसरा- कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा इसे एक्यूपंक्चर होता जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। पांचवां इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती है।
10. **यज्ञोपवीत** -यज्ञोपवित को उपनय या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिन्दू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानि यज्ञोपवित में तीन सूत्र होते हैं। ये तीन देवता- ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है।
11. **वेदारंभ** - इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है।
12. **केशांत**
13. **समावर्तन**
14. **विवाह**
15. **आवसथ्याधाम**
16. **श्रौताधाम**

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को पूरा करेंगे। तथा आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे कुछ लोगों और दूसरों तरह, आपसे भिन्न कार्य से लाभकारक साबित साबित। तब ये विधि हमारे साथ में और लाटरी सुर्यो को बुलवाते तथा लाभकारक ऊर्जा को सकृष्ट करेंगे, वरिष्ठ पुरुषरीति लोगों में भी, जहां तक लाभकारक हमें लोग और बाजीगर में लाभ प्राप्त करेंगा

मेष
व्यवसाय करने वालों को सरकार की तरफ से लाभ मिलने और नौकरीपेशा को उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि मिलेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

वृष
शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। उग्र वाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है।

मिथुन
पिता तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। मन आनंदित रहेगा। फिर भी स्वभाव में उग्रता का असर आपकी वाणी पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी।

कर्क
विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान के अध्ययन या अन्य मामलों के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगी। कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। सरकार से लाभ होने की संभावना है। भाग्य साथ न देता हुआ प्रतीत होगा।

सिंह
गृहस्थ जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। आय में वृद्धि होगी। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी। आज आपके हरेक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

कन्या
पाचन तंत्र संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से किसी को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। आज आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा करेंगे। नौकरी-धंधे में उच्च अधिकारी या भागीदार के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा।

तुला
किसी के साथ गलतफहमी होने के कारण मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। अत्यधिक धन खर्च होगा। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निर्णय के कारण आज आप कोई भी काम त्वरित निर्णय लेकर पूरा करेंगे।

वृश्चिक
आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। परिश्रम की अपेक्षा कम सफलता मिलने से निराशा रह सकती है। नौकरी और व्यापार के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे।

धनु
शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, स्नेहीजनों से लाभ होगा। शरीर में थकान और बेचैनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मन चिंता से व्याकुल रहेगा। आज यात्रा स्थगित रखने की सलाह दी जाती है। संतान के विषय में चिंता रहेगी।

मकर
कोर्ट-कचहरी का कामों को आज टाल देना हितकर है। आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा।

कुंभ
गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति होगी। अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा। संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा।

मीन
लंबे प्रवास का आयोजन संभव होगा। विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। दिन के दौरान आकस्मिक घटनाओं में व्यस्त रहेंगे। आज आप शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। परिणामस्वरूप मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे। आंख संबंधी शिकायत पैदा होगी।

डॉक्टर और कंपनियों का कपट जाल, दवाओं की कीमत में उछाल

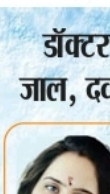

— प्रियंका सौरभ

नियमों में कहा गया है कि केवल ब्रिटिशनेम वाली दवा और ओवर-द-काउंटर दवा के प्रकार जो केवल फार्मेसियों में बेचे जा सकते हैं, उन्हें सभी फार्मेसियों में बिल्कुल एक ही कीमत पर बेचा जाना चाहिए। इसलिए, की दवाओं की कीमतें फार्मेसियों के बीच उतार-चढ़ाव नहीं करती हैं, जिसका अर्थ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना ब्रिटिशनेम कहने के लिए किस फार्मेसी को चुनते हैं। यही नहीं दवा बनाने वाली कंपनियों पर ये नियम सख्ती से लागू किये जाए कि वह हर साल का मूल्य भारत सरकार के नियमानुसार एक जैसा निर्धारित करे चाहे ब्रांड कोई भी हो। मूल्य ब्रांड पर न होकर साल्ट पर हो ताकि डॉक्टरों और कंपनियों के काले धंधे पर लगाम लगे और गरीब को 300 रुपये का इंजेक्शन बारह हजार में न साठीजना पड़े।

देश में दवाओं की क़ीमत सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं। डॉक्टर अपने मुताबिक ब्रांड बनवाते हैं। क़ीमत फिक्स करते हैं। 38 रुपए की दवा की एमआरपी 1200 रुपए कर दी जा रही है। यह महज़ एक एग्जाम्पल है, ऐसा तमाम दवाओं में किया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं, 20 साल में 40 हज़ार करोड़ से दवा का कारोबार 2 लाख करोड़ के पास पहुँच गया है। इसका बड़ा कारण वह एमआरपी में बड़े खेल को मानते हैं। 2005 से 2009 तक 50 प्रतिशत एमआरपी पर दवाएँ बिक रही थी। अगर 1200 रुपए की एमआरपी है तो डीलर को 600 रुपए में दी जाती थी। अब डॉक्टर अपने हिसाब से ही एमआरपी तय करवा रहे हैं। जबकि नियमों के अनुसार डॉक्टर दवाओं के रेट तय नहीं करते। दवाओं के रेट, दवा बनाने वाली कंपनियाँ तय करती हैं। दवाओं के रेट तय करने में कई कारक शामिल होते हैं। दवाओं पर व्यापारियों को अच्छा मुनाफ़ा होता है। ब्रांडेड दवाओं पर रिटेलर ज्यादा से ज्यादा 20-25 प्रतिशत तक की छूट देते हैं। जेनेरिक दवाओं पर 50-70 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। जेनेरिक दवाएँ सस्ती होती हैं क्योंकि उन्हें महंगी जांचों से नहीं गुज़रना पड़ता। दवा खरीदते समय, दवा के रैपर पर क्यूआर कोड होना चाहिए, दवा के रैपर पर क्यूआर कोड से दवा का नाम, ब्रैंड का नाम, मैन्युफ़ैक्चरर की जानकारी, मैन्युफ़ैक्चरिंग की तारीख और एक्सपायरी की तारीख मिलती है। दवाओं या उनके अवयवों के बारे में जानकारी के लिए, डॉक्टर या फ़ार्मासिस्ट से पूछा जा सकता है। मगर जो दवाएँ सरकार के कंट्रोल से बाहर, उनमें मनमानी दवा की क्वालिटी और एमआरपी की निगरानी के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल फ़ार्मास्युटिकल प्राइस अथॉरिटी काम करती है। सरकार इस प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से दवा की एमआरपी पर नियंत्रण रखती है। आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के साथ डीपीसीओ की जिम्मेदारी मरीजों के लिए दवाएँ सस्ती और सुलभ कराने की भी है। सरकार जिन दवा को डीपीसीओ के अंडर में लाती है, उनकी एमआरपी तो कंट्रोल में होती है, लेकिन सैकड़ों फॉर्मूले की दवाएँ आज भी सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, जिसको एमआर पी में मनमानी चल रही है। दवाओं की कीमतों में इजाफे को लेकर सरकार की गाइडलाइन है कि एक साल में 10 प्रतिशत ही एमआरपी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कंपनियाँ प्रोडक्ट्स का नाम बदलकर हर साल डॉक्टरों की डिमांड वाली एमआरपी बना रही हैं। कंपनियाँ अलग डिवीजन और ब्रांड बदलकर एमआरपी अपने हिसाब से फिक्स कर देती हैं। फार्मा फैक्ट्रियों से ही देश में दवाएँ सप्लाई की जाती हैं। कंपनियाँ और डॉक्टरों के इस खेल में कंपनियाँ अपने मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टरों के हिसाब से न सिर्फ़ दवाएँ बनाने को तैयार हो जाती है, बल्कि मनमानी क़ीमत भी तय कर देती है। यही नहीं इन कंपनियों से मोबाइल पर ही डील हो जाती है। तभी तो देश भर में डॉक्टर और हॉस्पिटल खुद अपनी दवाएँ बनवा ही रहे हैं और मनमाफिक मूल्य पर बेच रहे हैं।

शख्सियत — बढ़ता राजस्थान

श्री अंशदीप (आईएएस)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री अंशदीप 16 अगस्त सन 1989 को पंजाब में जन्में अंशदीप एक बेहतरीन आईएएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जहां भी रहे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ तालमेल के साथ व अपने उच्चस्थ अधिकारियों के साथ समन्वय के साथ कार्य किया। मुस्कान भरा चेहरा और गजब का आत्मविश्वास। बी टेक (सिविल इंजीनियरिंग) कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और आज उप सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली जैसे बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व वे उप सचिव, सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली रहे। अयुक्त आबकारी विभाग एवं पदेन महा निषेध निदेशक राजस्थान उदयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान अजमेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली। निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव राजस्थान जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा। सहायक सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) जोधपुर महानिदेशक अतिरिक्त कार्यभार डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन (अम्बेडकर पीठ) जयपुर निदेशक एवं संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन विभाग राजस्थान जयपुर ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम। इनके द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (भारत) प्रशिक्षण इनके द्वारा लिया गया। इसनिवत की शानदार परिभाषा इनके व्यक्तित्व से देखने को मिलती है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

2025_021 a — बढ़ता राजस्थान

Ans_2025_020

Suduko

8	7	5		9		4	6	
	4	9		6				8
	2	6	8	3			7	
4	8				2			9
	1	3	4	7	8	6		2
5			3	1	9	7		4
7					3	5		6
2	5			4	6		9	
	3	1	9		5	8	4	

6	7	9	1	8	2	3	4	5
4	2	3	7	9	5	8	6	1
5	1	8	3	4	6	9	7	2
1	9	2	6	7	3	5	8	4
8	5	7	4	1	9	6	2	3
3	4	6	5	2	8	7	1	9
9	8	4	2	5	7	1	3	6
2	3	5	8	6	1	4	9	7
7	6	1	9	3	4	2	5	8

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर- 18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन न.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार